● वर्ष-3
● अंक-281
रायपुर, गुरुवार
04 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जैव उर्वकों से बढ़ती फसल की..

चंपई का सीएम पद से इस्तीफा, हेमंत फिर से संभालेंगे कमान

नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे फिर से सीएम के रूप में हेमंत सोरेन की वापसी का मंच तैयार हो गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद पद

छोड़ने के लिए मजबूर होने के लगभग पांच महीने बाद, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आने के लिए तैयार हैं। सोरेन को 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी थी।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के आरोप का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। यह तीसरी बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री होंगे, जो 2000 में बिहार से अलग होकर बना था। चंपई सोरेन को यूपीए समन्वय समिति के अध्यक्ष और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नई जिम्मेदारी देने की भी चर्चा चल रही है।

इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी शामिल हुए। इस बीच, बीजेपी के आक्रामक होने की कहानी तय करते हुए, सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड में चंपई सोरेन युग खत्म हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि परिवारवादी पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।

काश आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बिरसा भगवान से प्रेरित होकर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जी के खिलाफ खड़े हो पाते? असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि झारखंड में झामुमो एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना अत्यंत दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड की जनता इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करेगी और इसे दृढ़ता से खारिज करेगी।

रायपुर। ये आपके पापा के बॉस है और इन्हीं के प्रयासों से आप सभी को स्कूल बस मिला है। आप सभी अब आराम से और सुरक्षित ढंग से स्कूल आ जा सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस परिवार के स्कूली बच्चों से चर्चा के दौरान गृहमंत्री का परिचय कराते हुए ये बातें कहीं। सभी बच्चों ने बस मिलने की खुशी में ताली बजाकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को थैंक यू कहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और खूब तरक्की करें।

भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हो गई है भारतीय न्याय संहिता

नई दिल्ली। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यह 1 जुलाई से प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है, जिसने दशकों पुराने ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदल दिया है। नए दंड संहिता के लागू होने के साथ, पूरे भारत में पहले ही कई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ तेज रफ्तार से जुड़ी हुई हैं।

तेलंगाना में, बीएनएस के तहत पहली प्राथमिकी सोमवार सुबह साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी बीएनएस (धारा 104) (लापरवाही के कारण मृत्यु होना) के तहत दायर की गई थी। यह एक ड्राइवर की मौत से संबंधित थी जिसने अपनी कार को पीएनवीआर एक्सप्रेसवे पर मेडियन से टकरा दी थी। नए दंड संहिता के तहत केरल में भी पहली प्राथमिकी एक व्यक्ति के खिलाफ तेज रफ्तार ड्राइविंग (धारा 281) के लिए दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवी अधिनियम) 1988 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

अखिलेश से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार

2009 के बाद भाजपा यूपी में ये खेलेगी बड़ा दांव!

नई दिल्ली। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम के तहत भाजपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। संभल सीट से निवर्तमान सपा विधायक जिया उर रहमान के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा अपने संगठन से एक वरिष्ठ मुस्लिम पदाधिकारी को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह पहली बार होगा कि भाजपा यूपी में विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को मैदान में उतारेगी। हालांकि उसने अतीत में लोकसभा चुनावों में अपने प्रमुख नेता मुख्तार अब्बास नकवी को मैदान में उतारा है। नकवी ने आखिरी बार 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब से, भगवा पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। सूत्रों ने कहा कि कुंदरकी में लगभग 60त्न मतदाता मुस्लिम हैं, यह सीट पार्टी ने कभी नहीं जीती है। बीजेपी के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि संगठनात्मक कमान पार्टी के एक मुस्लिम पदाधिकारी के संपर्क में है। बीजेपी नेता ने बताया, राज्य नेतृत्व उनके नाम को अंतिम रूप देने और अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार केरल की मलप्पुरम सीट से कालीकट विश्वविद्यालय के पूर्व

कुलपति अब्दुल सलाम थे। सलाम हालांकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के ईटी मोहम्मद बशीर से हार गए। यूपी में, पिछली बार बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली का समर्थन किया था, जिन्हें 2022 के राज्य चुनावों के दौरान सहयोगी अपना दल के टिकट पर रामपुर की सुअर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। अली सपा के अब्दुल्ला आजम से 60,000 से अधिक वोटों से हार गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में नकवी ने रामपुर से जीत हासिल की थी। 1999 में वह कांग्रेस की बेगम नूर बानो से सीट हार गए।

संसद सत्र में राहुल-अखिलेश में दिखी केमिस्ट्री

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आहूत संसद के विशेष सत्र का राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ आज सत्रावसान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेहरे पर संसद के सत्र का जिक्र करते ही मुस्कान तैर जाती है। इस सत्र में राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बालबुद्धि वाला और फेल बताया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं की धुरी बनकर उभरे हैं। सत्र के सत्रावसान के बाद सबसे अधिक चर्चा में भी राहुल गांधी और उनका 90 मिनट का लोकसभा में संबोधन है। दूसरी बड़ी चर्चा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बीच में बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर है। अखिलेश यादव ने

सत्र के आरंभ होने के दिन पहले अपने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को प्रमुखता से स्थान दिया। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अवधेश प्रसाद को पूरे सत्र के दौरान मान देकर साझा रणनीति को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तालमेल को महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री के आज राज्यसभा में संबोधन के दौरान इसकी गहराई महसूस की गई। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से कहा कि वह अपने भतीजे (अखिलेश) को समझाएं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण को अच्छा बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी के भाषण में कुछ भी गलत नहीं लगा। अखिलेश यादव ने राहुल के वक्तव्य पर भाजपा के नेताओं की टिप्पणी को भाजपा की रणनीति करार दिया।

मानहानि मामलाः ममता के वकील ने राज्यपाल पर साधा निशाना

राजनीतिक मुद्दों को प्रचारित करने का प्रयास बताया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने 28 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके एक दिन बाद बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे वहां होने वाली गतिविधियों के कारण राजभवन जाने से डरती हैं। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मानहानि के मुकदमे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन के बाद, ममता बनर्जी के कानूनी सलाहकार संजय बसु ने राज्यपाल पर निशाना साधा। बोस द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। संजय बसु ने कहा कि राज्यपाल का मानहानि मामला उनके द्वारा

अन्य राजनीतिक मुद्दों को प्रचारित करने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है, जैसे कि निर्वाचित सदस्यों को मानहानि की आड़ में अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेने से मना करना। हम इन आरोपों का उचित बचाव करेंगे। हमें पता चला है कि तृणमूल प्रमुख के कथित बयानों पर मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है.

ममता के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी है। बोस ने बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं की कथित टिप्पणियों को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

प्रमुख समाचार

अमरनाथ यात्राः टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड

अमरनाथ यात्रा ने पहले चार दिनों में 74,000 का आंकड़ा पार करके पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के पहले चार दिनों में, देश के विभिन्न हिस्सों से 74,696 तीर्थयात्रियों ने भगवान शिव की पवित्र गुफा में दर्शन किए। मंगलवार को 22,715 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिव लिंग के दर्शन किये। यात्रा शुरू होने के बाद पहले चार दिनों के दौरान गहरे हिमालय में स्थित पवित्र पर्वत गुफा मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 74,696 तक पहुंच गई है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बड़े पैमाने पर सुविधाएं लगाई गई हैं। पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों के लगभग एक लाख सुरक्षाकर्मियों को जम्मू आधार शिविर से कश्मीर आधार शिविरों तक तैनात किया गया है।

ब्रांड छवि बहाल करके अमरावती का पुनर्निर्माण किया जाएग

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि निवेशकों की विश्वास बहाली और ब्रांड छवि फिर से स्थापित करके अमरावती का पुनर्निर्माण शुरू किया जाएगा। वर्ष 2014 और 2019 के बीच तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की सरकार के दौरान संकल्पित हरित राजधानी शहर की स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अमरावती के बारे में केंद्र को सबकुछ बताएंगे और इसे निष्पादित करने के लिए तेजी से तथा समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। नायडू ने सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''अमरावती का पुनर्निर्माण कल से ही शुरू हो चुका है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सभी कानूनी बाधाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।'' उन्होंने कहा कि अमरावती का पुनर्निर्माण मौजूदा मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें आधुनिक चीजें भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिंगापुर ने अमरावती के लिए तीन मास्टर प्लान तैयार किए थे। सिंगापुर द्वारा विकसित योजनाओं के अनुसार, अमरावती में एक खेल शहर, सरकारी शहर, पर्यटन शहर, वित्त शहर, न्याय शहर, ज्ञान शहर, मीडिया शहर, स्वास्थ्य शहर और इलेक्ट्रॉनिक्स शहर यानी कुल मिलाकर नौ शहर होंगे।

10 साल की उम्र से ही बेटी के साथ महापाप कर रहा था अब्बाजान

नई दिल्ली। पाप, अति पाप और महापाप क्या है? रावण ने सीता का अपहरण किया, यह अति पाप है। इसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन, उसने साधु वेश में एक महिला का अपहरण किया, यह महापाप है और शिव पार्वती संवाद के मुताबिक इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। यह विश्वास को भंग करने का अपराध है। समाज या परिवार जिन पर आंख मूंदकर विश्वास करता हो, वे जब इस विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर किसी बहू या बेटी पर हाथ डालें, तो उसकी सजा कठोर से कठोरतम है। केरल के मल्लापुरम में एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने मोहम्मद एच को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो अधिनियम), भारतीय दंड संहिता, और किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के तहत 101 साल की जेल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते, अदालत ने 43 वर्षीय व्यक्ति को सजा सुनाते हुए लड़की पर अपराध के आजीवन प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

सिवान में 12 घंटे में दो पुल धड़ाम 10 दिन पहले भी गिरा था ब्रिज

सीवान। बिहार के सीवान जिले में गंडकी नदी पर बने दो पुल बुधवार सुबह भारी बारिश के बीच ढह गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पंद्रह दिनों में राज्य में यह सातवीं ऐसी घटना है। छोटे पुल महराजगंज को जिले के देवरिया ब्लॉक में स्थित आसपास के कई गांवों से जोड़ते थे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीवान में पिछले 11 दिनों में पुल ढहने की तीन घटनाएं देखी गई हैं। उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि सही कारण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 5 बजे के आसपास हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुल 1982-83 में बनाया गया था। कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पुल की मरम्मत चल रही थी। स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया कि पिछले दिनों में भारी बारिश के कारण ऐसा हुआ होगा। ढहने से गंडकी नदी में उफान आने से पुल की संरचना संभावित रूप से कमजोर हो जाएगी। एक और घटना में महराजगंज प्रखंड के धमही गांव में स्थित गंडक नदी पर बना हुआ था।

मणिपुर में स्थिति सामान्य नहीं हैः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि राज्यसभा में मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा कम हो रही है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लौट आये। रमेश ने एक्स पर कहा कि आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर महीनों की पूर्ण चुप्पी के बाद, गैर-जैविक पीएम ने आश्चर्यजनक दावा किया कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है। विपक्ष ने पहले आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जानबूझकर मणिपुर की स्थिति से मुंह मोड़ रहे हैं। संसद में उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने बार-बार मणिपुर से जुड़े नारे लगाए। रमेश ने कहा कि वास्तव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, जैसा कि आंतरिक मणिपुर के सांसद ने 1 जुलाई को लोकसभा में बताया था। और गैर-जैविक प्रधान मंत्री ने 3 मई, 2023 की रात को हुए विस्फोट के बाद से अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है और न ही उन्होंने राज्य के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की है। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी इस मुद्दे पर मौन था।

पूर्ण बजट : प्रतिस्पर्धी विचारों की जरूरत, ताकि संसाधनों का हो सके प्रभावी इस्तेमाल

शंकर अय्यर

बजट का इतिहास खुद में एक दिलचस्प यात्रा है। किवदंती है कि मध्ययुगीन फ्रांस में यायावर गीतकार बोगेट (बजट) में रखे गए अपने धन का प्रबंधन किसी संरक्षक को सौंपते थे, जिसे बजटकर्ता के रूप में जाना जाता था। ब्रिटेन में जब %बजट% शब्द का उपयोग होने लगा, तो इसने अपना प्रभामंडल और कद हासिल किया। 1400 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद महज एक याचिका निकाय थी, जहां सांसद अपनी शिकायतों के समाधान की मांग करते थे और राजशाही खर्च योजना को मंजूरी देती थी। 18वीं सदी तक, चांसलर द्वारा पेश किए जाने वाले बजट का उद्देश्य खर्च को कम करना और एक नए सामाजिक अनुबंध के अनुसार, राजा की कर लगाने की शक्ति पर अंकुश लगाना था।

आधुनिक काल में ब्रिटेन में कड़ी प्रतिद्वंद्विता के कारण छाया मंत्रिमंडल और छाया बजट की रूपरेखा तैयार हुई, जिससे संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण एवं योजनाएं पेश करने का मौका मिला। वास्तव में मौजूदा चुनाव में भी सट्टेबाजी और अन्य घोटालों के अलावा प्रमुख मुद्दा टोरिज और लेबर पार्टी के बीच वैचारिक प्रतिद्वंद्विता है। वैकल्पिक बजट केवल ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक में प्रचलित है। इसी महीने बाद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 2024ङ्क25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह कवायद ऐसे समय हो रही है, जब कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर घोषणापत्रों एवं बयानबाजी के जरिये अपने दृष्टिकोण पेश किए, जिनमें बेरोजगारी, कृषि संकट, महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल थे। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र (न्याय पत्र) में कई विचार पेश किए। भाजपा के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण %मोदी की गारंटी% की झलक स्पष्ट रूप में बजट में दिखेगी। आम तौर पर किसी भी बजट के बाद होने वाली बहस दावों और प्रतिदावों के शोर की प्रतिस्पर्धा होती है। इसके बाद विलाप का एक सुनियोजित कोरस होता है कि किसने किया और क्या नहीं किया। इस बहस में बजट आवंटन पर कोई सूचना नहीं होती। विपक्ष हमेशा दावा करता है कि इसे बेहतर किया जा सकता था। सवाल उठता है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को छाया मंत्रिमंडल बनाने से कौन रोकता है, जिसमें मंत्री मंत्रालयों की निगरानी करते हैं और एक प्रतिस्पर्धी बजट पेश करते हैं। विपक्षी गठबंधन अपने दावों को दस्तावेज के रूप में क्यों नहीं %दूध का दूध और पानी का पानी% की तरह साबित कर सकता?

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी तक विपक्ष की पहुंच है। फरवरी, 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में बुनियादी मैक्रो डाटा शामिल है। इसके अलावा, पूर्वानुमानों के अद्यतन आंकड़े भी उपलब्ध हैं-इसमें 2023-

24 के लिए जीडीपी के अनंतिम अनुमान, बेहतर प्रत्यक्ष कर संग्रह का विवरण, जीएसटी प्राप्तियों के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष, मौद्रिक नीति समिति के बयानों में विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान शामिल हैं। वैकल्पिक बजट को सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के एक या दो दिन पहले या बजट के एक दिन बाद जारी किया जा सकता है। बजट तैयार करना राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ने का विज्ञान और कला, दोनों है। यह देश के लोगों के लिए उपयोगी होगा, ताकि वे %विकास के एजेंडे को कैसे तैयार किया जाए% इस पर दोनों पक्षों के फोकस और दृष्टिकोण की तुलना कर पाएंगे। चुनाव अभियान ने मुद्रास्फीति, कृषि संकट और बेरोजगारी के मुद्दों पर बढ़ती चिंता और मध्यम वर्ग की कथित उपेक्षा की पीड़ा को उजागर किया। कांग्रेस के पास यह दिखाने का अवसर है कि वह किस तरह से अपने विचारों को सामने रखेगी और अर्थव्यवस्था को गति देगी। मसलन, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और प्रति वर्ष एक लाख रुपये का भुगतान, प्रत्येक गरीब परिवार को एक लाख रुपये बिना शर्त नकद हस्तांतरण की महालक्ष्मी योजना। यह कोई रहस्य नहीं है कि नोटबंदी, जीएसटी की शुरुआत और कोरोना महामारी जैसे कई व्यवधानों के कारण राज्यों में कई अनौपचारिक उद्यम और एमएसएमई बंद हो गए। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के ताजा वार्षिक सर्वे के विश्लेषण से पता चलता है कि 18 लाख उद्यमों के बंद होने से 50 लाख से ज्यादा नौकरियों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में कौशल विकास वृत्ति द्वारा सक्षम एक मॉडल कार्यक्रम या 'आकांक्षी जिलों' में एक बड़ा कार्यक्रम पेश कर सकता है। यह भी सबको मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत और उपलब्धता के बीच भारी अंतर है। विपक्षी पार्टियां स्वास्थ्य और अन्य पहलों के विस्तार के लिए एक फंडिंग योजना की रूपरेखा बना सकती हैं, साथ ही विकास को समर्थन देने के लिए एक विधायी एजेंडा भी बना सकती हैं। वैकल्पिक बजट विपक्षी गठबंधन को यह दिखाने का मौका दे सकता है कि संसाधनों (जैसे बढ़े हुए राजस्व और आरबीआई के अधिशेष) को बेहतर परिणामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। इसके लिए विपक्षी गठबंधन पूर्व वित्त मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों जैसे जानकार लोगों को इकट्ठा करके इस कार्य के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है।

ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट

कोहकामेटा नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवान थे निशाने पर

नारायणपुर। नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों पर लगातार प्रहार जारी रखा है। इस साल के शुरुआत से ही यहां नक्सलियों पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। मंगलवार को कोहकामेटा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया। जब फोर्स की टीम सर्चिंग ऑपरेशन से लौट रही थी तभी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया।

अबूझमाड़ में कोहकामेटा के जंगलों में चलाए गए नक्सल ऑपरेशन को सकुशलता पूर्वक अंजाम देने के बाद सुरक्षा बलों के जवान लौट रहे थे। तभी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। अचानक हुए इस आईईडी विस्फोट में फोर्स के जवान बाल बाल बचे। धमाके के बाद फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की। जिसके बाद नक्सली मौके से भाग निकले।

नारायणपुर के जंगलों में अभी भी सुरक्षाबलों की टीम नक्सल ऑपरेशन को चला रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जंगलों में अब भी मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि नक्सल ऑपरेशन के बाद गुरुवार सुबह तक सुरक्षाबलों के जवान वापस लौटेंगे। सभी जवान नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे

कोहकामेटा नक्सल एनकाउंटर में पांच नक्सली अब तक मारे गए हैं। मंगलवार को तीन नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई। उसके बाद शाम तक पांच नक्सलियों के मारे जाने की खबर पुष्ट हुई। अब सर्चिंग ऑपरेशन के बाद सही आंकड़ा सामने आएगा।

अबूझमाड़ नक्सलियों का मांद कहा जाता है। इस इलाके को नक्सली अपनी रिहायश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्चिंग ऑपरेशन के बाद मौके से सुरक्षाबलों को 4 नग थ्री नॉट थ्री रायफल मिली है। एक बारह बोर की बंदूक मिली है। इसके साथ ही नक्सलियों का भारी मात्रा में डंप भी बरामद हुआ है। जिसमें दैनिक उपयोग की चीजें हैं।

आईईडी ब्लास्ट की जांच करेगी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईटीबीपी के दो जवान हुए थे घायल

छत्तीसगढ़ के नवगठित स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट केस की जांच करेगी। नक्सली, गौ तस्करी समेत संदिग्ध मामलों में जांच करने के लिए बनी एसआईए गठन के बाद से कोई भी केस नहीं था। अब यह पहली केस है, जिसका एसआईए जांच करेगी। 14 जून को नक्सलियों के प्लांट किए गए आईईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल हुए थे। इस मामले में अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से जल्द टीम गठित कर घटनास्थल पहुंचकर जांच करेगी। साथ ही हादसे में घायल और हादसे के दिन मौके पर मौजूद जवानों से पूछताछ की जाएगी।

बता दें कि नारायणपुर ब्लास्ट मामले में एनआईए अब तक जांच शुरू नहीं की है। ऐसे में एसआईए के अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दी। अब इस मामले की जांच के लिए एसआईए जल्द टीम गठित करेगी। इसके बाद घटना स्थल पहुंचकर घायल समेत जवानों से बात करेगी। इससे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और साक्ष्य जुटाया जा सके। इसलिए एसआईए ने यह कदम उठाया है। अब इस मामले में एसआईए की टीम विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने इस जांच की पुष्टि की है।

नारायणपुर जिले के कुतुल और मोहंदी के बीच जंगलों में 14 जून को आईटीबीपी के जवान एरिया डोमिनेशन में निकले थे। इस दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट की गई आईईडी के चपेट में आने से आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए थे। घायलों में एसी धर्मेंद्र और कांस्टेबल नारद कुमार शामिल थे। दोनों को इलाज के लिए नारायणपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद घायल जवानों को हेलीकाप्टर के सहायता से रायपुर भेजा गया था, जहां उनकी इलाज जारी है।

राजस्व मंत्री आज करेंगे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

धमतरी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा 04 जुलाई को धमतरी जिले के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में विभागवार एजेंडा अनुसार विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

बैठक के एजेंडा अनुसार राजस्व विभाग अंतर्गत जिले के राजस्व न्यायालयों में प्रकरण निराकरण की स्थिति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं त्रुटि सुधार, शिकायतों का निराकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा, श्रमिकों की संख्या, निर्माण कार्यों की स्थिति, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत सशक्तिकरण योजना, एनआरएलएम, बजट आबंटन, आरईएस अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य, पंचायतो में वाई फाई, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शाला प्रवेश उत्सव, माध्यन्ह भोजन, शिक्षक विहीन शाला, निर्माण कार्य की स्थिति, शाला भवनों की जर्जर स्थिति, आय, जाति निवास प्रमाण पत्र, समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा की जाएगी।

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत वनाधिकार पत्र, आश्रम-छात्रावासो की स्थिति, पीएम आदर्श ग्राम योजना, उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला व्यापार केंद्र, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमइजीपी, रोजगार सृजन कार्यक्रम, कृषि विभाग के अंतर्गत खाद बीज़ भंडारण एवं वितरण, बुआई की स्थिति, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, किसानों की समस्या का निराकरण, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुपालन के लिए केसीसी, अनुदानो की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मौसमी बीमारियों के रोकथाम के उपाय, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, जीवन दीप समिति, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री पूरक पोषण आहार योजना, आंगनबाडी केंद्र, मातृत्व वंदन योजना, कुपोषण की स्थिति, पीएचई के अंतर्गत जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता की स्थिति, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांधों में जल भराव की स्थिति, नहरों की सफाई, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य, बजटीय स्वीकृति, सेतु निर्माण, भारतमाला परियोजना, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीडीएस भंडारण, धान भंडारण एवं उठाव, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत साफ सफाई, पेयजल, पीए आवास, शहरी आजीविका मिशन, वन विभाग के अंतर्गत तेंदुपत्ता वितरण, चरण पादुका योजना, वृक्षारोपण, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रामलला दर्शन योजना, दिव्यांगों के लिए आजीविका मूलक कार्य, उपकरण वितरण के साथ ही अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

किराना दुकान में मिला पीडीएस का चावल प्रशासन ने जब्ती के बाद दुकान को किया सील

जगदलपुर। जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर खाद्य विभाग की नजर है। इस कड़ी में तीन दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटित चावल व अन्य खाद्य सामग्री मिलने पर जब्ती की कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

दरअसल, गरीब परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर अब कई चावल माफिया की नजर है। पीडीएस चावल की कालाबाजारी को लेकर खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए चावल माफियाओं पर शिकंजा कसा है। शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित किराना दुकानों की पिछले दिनों जांच की गई, इस दौरान तीन दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत आबंटित चावल व अन्य खाद्य सामग्री मिलने से उसे जब्त करते हुए किराना स्टोर्स संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।

बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम का कहना है कि जिले में पीडीएस के तहत वितरण होने वाले चावल व अन्य खाद्य सामग्री को राशन कार्डधारियों द्वारा किराना स्टोर्स के व्यापारियों को बेचने की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के द्वारा शहर के कई दुकानों में दबिश देकर जांच की गई। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर तीन दुकान को सील कर दिया गया।

जिला खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में पीडीएस चावल की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर शहर के भंगाराम चौक स्थित अशफाक नगानी के किराना दुकान में दबिश देकर 21 बोरा चावल जब्त किया गया। इसके अलावा अम्बेडकर वार्ड में पिकअप वाहन से 17 बोरा चावल बरामद कर जब्त किया। इसके साथ ही कुम्हारपारा रमन किराना स्टोर्स से 27 बोरा और गीदम रोड़ पर पिकअप वाहन से 60 बोरा राशन चावल जब्त कर कार्रवाई की गई है।

किसानों की जमीन पर बनी बांध का अब तक नहीं मिला मुआवजा

- **बांध का आकार बढ़ने से डुब गई 250 एकड़ जमीन, मुआवजे के लिए शासन-प्रशासन से लगाई गुहार**

खैरागढ़। देश में जलाशय का निर्माण किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन बड़े बांध बनाने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े जंगल और कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है। अधिग्रहण का उचित मुआवजा भी दिया जाता है। ऐसा ही एक बांध 1988 में ग्राम उरईडबरी में बनाया गया, जिसके लिए किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला।

खैरागढ़ जिले के ग्राम परसबोड और उरईडबरी के किसान अपनी डुबान खेती की जमीन के मुआवजे के लिए सालों से शासन-प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, परंतु अब तक उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। एक बार फिर क्षेत्र के किसान खैरागढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर एडीएम प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपा।

पीड़ित किसान नीलेश्वर साहू की माने तो 1988-89 में बने इस बांध में क्षेत्र के किसानों की जमीन लगातार डूबती जा रही है और लगातार बांध का आकार बढ़ने से किसानों का खेत भी डुबाना क्षेत्र में आ रहा है। इसमें अब लगभग 250 एकड़ जमीन किसानों का डुबान क्षेत्र में आ गया है। इस किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग कलेक्टर से की गई है।

इस मामले में एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बने इस जलाशय को लेकर किसानों के जमीन का अधिग्रहण 1988-89 में किया गया था। इसे लेकर किसानों की मांग है कि उन्हें अब तक अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। पूर्व में दिए गए आवेदनों एवं दस्तावेजों की जांच अनुभागीय अधिकारी से कराई जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

फिल्मी अंदाज में बाइक सवार दो युवक लाखों के जेवर लेकर फरार

- **पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर**

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार की रात चक्रधर नगर चौक स्थित ओम ज्वैलर्स के यहां फिल्मी अंदाज में बाइक सवार दो अज्ञात लोगों द्वारा सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही चक्रधर नगर पुलिस टीम के अलावा स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच चुके हैं।

जानकारी के अनुसार शहर के चक्रधर नगर चौक में स्थित ओम ज्वेलर्स के संचालक द्वारा रोजाना की भांति दुकान बंद करने से पहले आभूषणों को अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगह रखवाया जाता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम भी दुकान बंद करने से पहले संचालक के द्वारा अपनी दुकान में रखे सोनें चांदी से भरे दो बैग तैयार करके अपने कर्मियों के माध्यम से भिजवाया गया। कर्मचारी आभूषण से भरा बैग लेकर जब निकले और कुछ दूर ही पहुंच पाये थे कि इसी बीच पल्सर सवार दो अज्ञात शख्स फिल्मी अंदाज में उनसे बैग छीनकर फरार हो गए।

उठाईगीरी की सूचना दिये जाने पर तत्काल चक्रधर नगर पुलिस, साइबर टीम के साथ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल मौके पर पहुंचे और आरोपियों की पतासाजी के लिये तत्काल शहर के चारो तरफ नाकेबंदी कराने के बाद चार अलग-अलग टीमें बनाकर अभियान तेज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आभूषण से भरे बैग में लाखों रुपये के जेवरात थे। कहा जा रहा है कि बदमाशों मे रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रेलवे प्रबंधन की मनमानी को लेकर प्रदर्शन कर फूंका पुतला

कोरबा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कोरबा रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे प्रबंधन की मनमानी और ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने बिलासपुर डीआरएम का पुतला भी फूंका। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रबंधन की मनमानी और गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियों को पुन: प्रारंभ करने को लेकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के महामंत्री मधुसूदन दास ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की मनमानी अपने चरम पर है ट्रेनों की लेटलतीफी से हर कोई परेशान है। यहां से कोयला परिवहन कर करोड़ों रूपये कमा रहे हैं लेकिन सुविधा के नाम पर छला जा रहा है।

कलेक्टर और सीईओ ने किया पौधरोपण

जगदलपुर। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर कलेक्टर श्री विजय दयाराम के परिवार के साथ अपने शासकीय निवास के परिसर में पौधरोपण किया। इसी प्रकार जिला पंचायत सीईओ श्री प्रकाश सर्वे ने भी अपने निवास में पौधरोपण किया। इस अवसर पर वन विभाग का अमला भी मौजूद रहा। ज्ञात हो कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंम्भ किया है, और देशवासियों के साथ दुनियाभर के लोंगो से आग्रह किया है कि वे अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाये। बस्तर में वन विभाग के सौजन्य से एक पेड़ माँ के नाम थीम पर निश्शुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है।बस्तर वनमंडल द्वारा 01 जुलाई से हरियाली प्रसार योजना के तहत भी पौधो का निश्शुल्क वितरण किया जा रहा है।

रामानुजगंज में अंतरराज्यीय लकड़ी तस्कर गिरोह एक्टिव

बलरामपुर। रामानुजगंज के वन परिक्षेत्र धमनी के सुंदरपुर गांव के आसपास अंतराज्यीय लकड़ी तस्कर गैंग सक्रिए है। बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई का मामला सामने आया है। तस्करों ने लगभग 10 ट्रैक्टर से ज्यादा लकड़ियां काट दी है। जंगल में पेड़ों की कटाई रात के अंधेरे में की जा रही है। लेकिन इन लकड़ियों को तस्कर जंगल में ही रखे हुए हैं। सुंदरपुर नर्सरी में 10 ट्रैक्टर से ज्यादा लकड़ियां का भंडारण किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी मात्रा में रखी हुई लकड़ियों पर फॉरेस्ट विभाग की नजर तक नहीं पड़ी। इधर राजस्व विभाग भी पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले में वन परिक्षेत्र के रेंजर अजय वर्मा ने बताया कि जहां भी लकड़ी भंडारित की गई है उसकी जांच कराई जा रही है। मामले में क्षेत्र के तहसीलदार को भी पत्र लिखा गया है। जितने भी लकड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से या लावारिस हालत में है उसे जब्त किया जाएगा। बलरामपुर में हाथी, भालू, तेंदुए के साथ ही कई संरक्षित प्रजाति के जीव जंतुओं का रहवास है।

दर्शन करने मंदिर जा रहे युवकों की कार पलटी

जगदलपुर। जगदलपुर में आसना के आगे मोड़ में बुधवार की दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी मारते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि बुधवार को एक कार जगदलपुर से गिरोला मंदिर दर्शन करने के लिए युवकों की टीम जा रही थी, कि अचानक मोड़ में ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ने से कार 2 पलटी मारते हुए पलट गई, कार में सवार लोग गाड़ी के बाहर फेंका गए और सड़क किनारे जा गिरे, आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी ने अपने पैट्रोलिंग वाहन को भी मौके के लिए रवाना किया, घटना के बाद घायलों को 112 की मदद से अस्पताल ले जाया गया, घायलों में संतोष और ईश्वर को गंभीर चोट लगने के कारण मेकाज में भर्ती किया गया है।

मिनी गोवा में नहाने के दौरान तीन युवक बहे, सुरक्षित

जगदलपुर। चित्रकोट जलप्रपात के एक किमी पहले कच्चे मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले मिनी गोवा के नाम से मशहूर बीच में नहाने के दौरान के तीन दोस्त बह गए। उन्होंने जान बचाने के लिए नदी के बीच बड़े पत्थर को पकड़ लिया। वहीं, युवकों को बहता देख कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद वहां पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने पांच घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तीनों युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक, जगदलपुर के तीन युवक जिसमें चेतन बघेल 25 वर्ष, लखेश्वर बघेल 30 वर्ष व नितेश कुमार कुर्रे 28 वर्ष आदि मंगलवार की शाम को मिनी गोवा में नहाने के लिये गए हुए थे। नहाते समय पानी के आगे बढ़ गए, गहराई के साथ ही पानी का बहाव तेज होने के कारण तीनों बहने लगे। बहने के दौरान नदी के बीच पत्थर को युवकों ने पकड़ लिया और मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही नगर सेनानी संतोष मार्बल तत्काल ही एसडीआरएफ की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे।

कीचड़ भरे रास्ते में एम्बुलेंस का जाना हुआ मुश्किल तो स्ट्रेचर लेकर पहुंचे गर्भवती महिला के घर

नारायणपुर। नक्सल प्रभावित और जंगलों से घिरे अबूझमाड़ इलाके में 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से सफल प्रसव कराया गया है। प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को 108 एम्बुलेंस की टीम ने 2 किलोमीटर तक स्ट्रेचर की मदद से पैदल चलकर एम्बुलेंस तक लेकर आ रही थी। लेकिन एम्बुलेंस तक पहुंचने से पहले ही महिला की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। जिसके बाद परिजनों की अनुमति मिलने पर बीच रास्ते में ही ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने सूझबूझ से सफल प्रसव कराया। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा ले जाकर भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार, ओरछा ब्लॉक के मंडाली गांव कि गर्भवती महिला सोमारी पति महरू 30 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने संजीवनी 108 से संपर्क किया। सूचना मिलने पर ओरछा 108 से ईएमटी कमला और पायलट राजेश गांव की ओर निकले। बारिश के कारण रास्ता खराब होने के कारण गांव से दो किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस को रोकना पड़ा, क्योंकि कीचड़ में एम्बुलेंस के फसने का डर था और एम्बुलेंस टीम पैदल ही पीड़िता के घर पहुंची। जिसके बाद स्ट्रेचर की मदद से गर्भवती महिला को दो किलोमीटर लाया गया।

एम्बुलेंस के पास पहुंचने से पहले ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई, जिसके बाद परिजनों से सलाह कर ईएमटी ने रास्ते में ही प्रसव प्रक्रिया प्रारम्भ किया। स्ट्रेचर के चारों तरफ कपड़े का पर्दा बनाकर घेरा किया गया और प्रसव कराया गया। इसमें मितानिन ने भी सहयोग किया। सफल प्रसव के बाद मां और बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में भर्ती कराया गया। फिलहाल, दोनों स्वस्थ हैं।

सात समंदर पार से पहुंचे विदेशी मेहमान बताएंगे इस साल कैसी होगी बारिश

कोरबा। मानसून का संदेश लेकर खूबसूरत प्रवासी पक्षी कोरबा के कनकी पहुंच चुके हैं। कोरबा का कनकेश्वर धाम आसपास के जिलों में बाबा धाम के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की आराधना के साथ कनकी को प्रवासी पक्षियों के रहवास के लिए भी जाना जाता है। जहां जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में खूबसूरत एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड अपना घोंसला बनाते हैं। अपने प्रजनन काल का समय ये पक्षी इन्हीं घोसलों में बिताते हैं। बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर में वापस उड़ जाते हैं। भारत के साथ ही एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं। इस वजह से इन्हें प्रवासी पक्षी की संज्ञा दी जाती है।

कनकी में मानसून की शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षी पहुंच जाते हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में होती है। ऐसा माना जाता है कि यह मानसून का संदेश लेकर पहुंचते हैं। जब पक्षी कनकी पहुंचने लगे तो यह मान लिया जाता है कि मानसून आ चुका है। कनकी का वातावरण इन पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल है। हसदेव नदी का किनारा, पीपल पेड़ और दूर तक फैले, मैदान और खेत इन पक्षियों को अच्छा वातावरण देते हैं, इस वजह से ये प्रवासी पक्षी दशकों से कनकी में मौजूद शिव मंदिर के आसपास के पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करते हैं।

मानसून के आगमन के साथ ही किसान अपने फसल की बुवाई भी शुरू करते हैं। यह पक्षी एक तरह से किसानों के मित्र होते हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट, पतंग को वह अपना भोजन बनाते हैं और इस तरह वह फसलों को नुकसान पहुंचने से रोकने में किसानों की मदद भी करते हैं। यह पक्षी पूरे मानसून के दौरान जब तक की फसल पककर तैयार ना हो जाए। तब तक पेड़ों पर निवास करते हैं। कोरबा में कनकी के साथ ही छत्तीसगढ़ के और भी कई इलाकों में इन पक्षियों के मौजूदगी है। जहां वह प्रजनन काल के लिए प्रवास पर आते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें घोंघिल पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। जो लंबी और आकर्षक चोंच वाले होते हैं।

भारत के साथ ही एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड दक्षिण पूर्व एशिया सहित चीन, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, वियतनाम थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमारजेड मलेशिया सिंगापुर और साइबेरिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। दुनिया के कई देशों में इनकी मौजूदगी है। सामान्य पक्षियों की तुलना में इनका आकार काफी बड़ा होता है। लंबी चोंच के कारण यह काफी खूबसूत दिखते हैं। कोरबा वन मंडल के डीएफओ अरविंद पीएम ने बताया कि एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड अपने प्रजनन के लिए हर साल कनकी में आते हैं। यहां उन्हें उपयुक्त वातावरण मिलता है। जिसके कारण वह कनकी में पेड़ पर अपना आशियाना बनाते हैं। काफी मात्रा में वो यहां पहुंचते हैं, वह जून के अंत में यहां जाते हैं और नवंबर, दिसंबर तक यहां रहते हैं। वन विभाग का प्रयास है कि उन्हें उपयुक्त वातावरण दिया जाए और लोगों में भी जागरूकता फैला रहे हैं। ताकि वह पक्षियों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचायें।

संक्षिप्त समाचार

नकली होलोग्राम केस में यूपी एसटीएफ शराब कंपनियों पर करेगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ ने शराब बनाने वाली कंपनियों पर दो बार नोटिस जारी कर चुका है। भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है, नोटिस मिलने के बाद भी कंपनियों से कोई भी दफ्तर नहीं पहुंचे। मामले में अब इन कंपनियों के संचालकों पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। यूपी एसटीएफ ने तीनों डिस्टलरीज को 10 जून को दूसरा नोटिस जारी किया था। यूपी एसटीएफ ने नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया था। नोटिस मिलने के बाद भी तीनों डिस्टलरीज के कोई भी अधिकारी यूपी एसटीएफ के दफ्तर में नहीं पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि मामले में एक बार फिर तीसरी बार तीनों एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाएगा। तीसरी बार नोटिस जारी होने के बाद अगर कोई भी पूछताछ के लिए शामिल नहीं होता है, तो एजेंसियों के संचालकों को हिरासत में लिया जा सकता है। इसके बाद पूछताछ की जाएगी।

राज्यपाल हरिचंदन से जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट धमतरी के पदाधिकारियों ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से

बुधवार को राजभवन में श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट धमतरी के अध्यक्ष श्री किरण कुमार गांधी के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। ट्रस्ट की ओर से राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और 106 वां रथयात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। इस अवसर पर सर्वगुजराती समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रीतेश गांधी, मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री लखम सिंह भानुशाली, सहसचिव श्री मोहन अग्रवाल, श्री भरत सोनी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को मिलेगी गति

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए यूनिसेफ को आमंत्रित किया है। इस सहयोग के तहत यूनिसेफ मुख्य रूप से नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। जुलाई 2024 से जुलाई 2026 तक की इस द्विवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में इस परियोजना का वृहद क्रियान्वयन किया जाएगा। यूनिसेफ मुख्य रूप से नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में न केवल स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा बल्कि स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, बाल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य करेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभी विभाग उचित वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे। इस परियोजना के माध्यम से सरगुजा संभाग विशेषकर जिला मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में यूनिसेफ की ओर से प्रभारी राज्य प्रमुख श्री विलियम हैनलोन , स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ गजेंद्र सिंह व पोषण विशेषज्ञ डॉ अपर्णा देशपांडे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल, आकर्षक बनते गांवों के स्कूल

रायपुर। शहरों के साथ-साथ गांवों के भी स्कूल अब आकर्षक बनते जा रहे हैं। नए शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश दिलाने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। महासमुंद, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले में एक हजार 991 स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद सभी जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी आई है। स्कूलों को आकर्षक ढंग से भी सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किए जा रहे जीर्णोद्धार में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पक्की छत, कक्षाओं में टाईल्स और शाला परिसर में पेवर ब्लॉक के साथ रंगरोगन का कार्य किए जा रहे है। इन स्कूलों में ज्ञानवर्धक और कलात्मक चित्रकारी भी की जा रही है।

राजस्व मंत्री ने पेड़ लगाकर एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान की शुरुआत

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने के आह्वान पर आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में नीम पेड़ लगाकर जिले में अभियान की शुरुआत किया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन वनमंडल बलौदाबाजार के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, डीएफओ मयंक अग्रवाल ने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम पर रोपण किया। कार्यक्रम में श्री वर्मा ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोडने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की। इसके साथ ही जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटलों एवं आंगनबाडियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री साय का दूसरा जनदर्शन आज

प्रदेशभर से आए लोगों की समस्या सुन करेंगे समाधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीते 27 जून को इस साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया गया था। इसी कड़ी में अब दूसरे जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कल यानि गुरुवार 4 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जनदर्शन के दौरान आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की

मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को दिया जाएगा।

29 जून को हुआ था पहला जनदर्शन

बता दें की मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 27 जून को सीएम साय के पहले जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण करने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव समेत रायपुर जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

साय ने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए किया बस सेवा शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परिवार के बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए बस का शुभारंभ किया। वहीं इस बस को डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएसआर मद से बच्चों को बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि आवासीय पुलिस कॉलोनी के बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, गृह मंत्री की पहल पर आज बस मुहैया कराया गया है। विधिवत पूजा करके शुभारंभ कर रहे हैं। सीएम साय ने पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को बस की चाबी सौंपी। इस मौके पर पुलिस परिवार के लोगों ने सीएम साय और डिप्टी सीएम शर्मा का आभार प्रकट किया। सीएम साय ने गृह मंत्री विजय शर्मा को उनकी इस पहल के लिए सराहना करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि और भी अन्य कंपनियों से आग्रह करेंगे इस प्रकार की पहल हो। वहीं हाथरस की घटना पर सीएम साय ने कहा कि हाथरस की घटना दुखद है। श्रद्धांजलि अर्पित करते है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। सरकार इसकी जांच करा रही है।

हमारी सरकार में सभी की शिकायत सुनी जा रही: उपमुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही। इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पहले आंकड़ों के फेर में लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। हमारी सरकार में हर किसी की शिकायत दर्ज की जा रही है। प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण किया जा रहा है।

हाथरस की घटना के बाद बड़े आयोजनों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है। सभी आयोजनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने यह सुनिश्चित करेंगे।

पीएचक्यू में कई अफसरों के पास वर्कलोड, कुछ अफसर के पास काम नहीं, इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अफसरों के बीच जल्द नए सिरे से कार्य विभाजन होगा। सभी को कार्य का बराबर अवसर मिले, ऐसा निर्णय लेंगे।

छत्तीसगढ़ में पिंक थाने खुलेंगे। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, महिला थानों की घोषणा बीजेपी के घोषणा पत्र में है। 5 महिला थानों की स्वीकृति बजट में है। आगे की प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ होगी। अन्य जिलों में भी थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए तीन कानून लागू हुए हैं उसमें भी आवश्यक है कि यह थाने खुले। पिंक थाने महिलाओं के लिए बनेंगे। महिलाएं अपनी बात आकार यहां रख पाएंगे।

फौती, नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण के लिए गांवों में लगेंगे शिविर

रायपुर। अब किसानों और भू-स्वामियों को फौती, नामांतरण, बंटवारा जैसी समस्याओं को लेकर दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जाएगी।

राजस्व पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे: फौती, नामांतरण एवं बटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही आनलाइन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा कर प्रविष्टि एवं मौके पर ही नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराकर निराकरण करने को कहा गया है। शिविर स्थल पर ही बी-1, खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाइन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अविनाश चंपावत से प्राप्त जानकारी के

अनुसार राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत राजस्व न्यायालय से संबंधित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय-सीमा में कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय-सीमा के बाहर प्रकरणों तथा सभी राजस्व न्यायालय में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों का 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों के सीमांकन प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण किया जाना है। विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन और धारा 115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि हेतु आवेदन प्राप्त कर तथा इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए 31 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निराकरण नहीं करने वाले राजस्व अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा।

राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि इसी तरह सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी सुनवाई तिथि अद्यतन नहीं है, उनका शत-प्रतिशत सुनवाई तिथि अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है। इसके साथ जनहानि-पशुहानि, फसल क्षति से संबंधी आर.बी.सी.6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने कहा गया है। राजस्व अधिकारी अधीनस्थ टेबल का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन 15 जुलाई तक कलेक्टर को उपलब्ध कराएंगे। राजस्व पखवाड़ा में भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन के प्रकरणों में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन करने सुनिश्चित करेंगे।

राजस्व पखवाड़ा में भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के अंतर्गत स्वामित्व योजनांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप-02 का 31 जुलाई 2024 तक प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना है। इसी तरह कोटवारो द्वारा विक्रय की गई कोटवारी और सेवाभूमि के विरूद्ध 31 जुलाई 2024 तक समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्षिकी कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन (जिंसवार) वर्ष 2023-24 का 15 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख शुद्धता के अंतर्गत संकलन हेतु शेष खसरा, विलोपन योग्य संदिग्ध खसरा, शून्य रकबा वाले खसरा, भूमिस्वामी विहीन खसरा, भूमिस्वामी के विवरण में स्पेशल कैरेक्टर युक्त खसरा, संयुक्त खातेदार का नाम पृथक-पृथक दर्ज न होकर एक साथ दर्ज होने, त्रुटिपूर्ण खसरा, भूमिस्वामी क्रमांक निर्धारण हेतु शेष खसरा की संख्या अंतर्गत 31 जुलाई 2024 तक शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण

■ **जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने मंगाए आवेदन**

रायपुर। जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित रायपुर ने आवेदन मंगाया है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किया जा सकेगा।

आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे- बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, कोचिंग क्लासेस एवं स्व-सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सेलून-ब्यूटी पार्लर, चाय केन्टीन एवं नास्ता केन्द्र, योग शिक्षा, बच्चों की देख-भाल (झूलाघर), लॉन्ड्री कार्य, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, घर की साज-सज्जा, बागवानी एवं नर्सरी पशुपालन एवं मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मशाला उद्योग, सॉफ्ट-टायज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की देखभाल, चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी

दुकान, सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईंट-खपरा निर्माण, डिटर्जेन्ट पाउडर निर्माण, लघु वनोपज वनौषधि निर्माण एवं व्यवसाय इलेक्ट्रीक मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय, खनिज आधारित व्यवसाय, कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत व्यवसाय, टाट-पट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, रेडियो टी.वी. टेप रिपेयरिंग व्यवसाय, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, किराना दुकान, फैन्सी (मनिहारी) व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, बर्मी कम्पोज मेकिंग, फॉस्ट फूड सेन्टर, एगरोल सेन्टर आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करना होगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम दस हजार रुपए का अनुदान देय है, परंतु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नहीं है।

नो योर आर्मी कार्यक्रम का 5 और 6 अक्टूबर को रायपरु में किया जाएगा आयोजन

यहां के बच्चों को चुनकर देश भर के फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में थल सेना के ब्रिगेडियर श्री अमन आनंद ने सौजन्य मुलाकात की। वे वर्तमान में भारतीय थल सेना के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया के कमांडर हैं। मुलाकात के दौरान ब्रिगेडियर श्री आनंद ने मुख्यमंत्री के समक्ष छत्तीसगढ़ में आर्मी की आगामी कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की।

ब्रिगेडियर श्री आनंद ने बताया की भारतीय थल सेना आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को और विशेषकर बच्चों को आर्मी के बारे में विस्तार से जानने और समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहां के बच्चों को चुनकर देश भर के फौज के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। इससे इन बच्चों में आर्मी के अनुशासन, देश प्रेम, सेना का देश के प्रति योगदान को जानने और इसमें शामिल होने का उत्साह जगेगा। ब्रिगेडियर श्री आनंद ने बताया की नो योर आर्मी कार्यक्रम में आर्मी के युद्ध में काम आने वाले हथियारों सहित अन्य विधाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदर्शित टैंक, तोप, हवा में मार करने वाले हथियार, ब्रिजिंग इक्विपमेंट सहित अन्य हथियारों के बारे में यहां के लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही डॉग शो, आर्मी में बजने वाले आकर्षक बैंड शो, मार्शल म्यूजिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा।

कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल:- govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com दूरभाष एवं फैक्स क्र. 0771-2263437

क्रमांक / क्रय/2024/745 दिनांक 01/07/2024

निविदा निरस्तीकरण सूचना

उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 717, दिनांक 24.06.2024 के द्वारा पैकिंग सामाग्रियां क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसे दिनांक 25.07.2024 को दोपहर पश्चात् 03:00 बजे खोला जाना था।

उक्त निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 717, दिनांक 24.06.2024 को अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

जी-242500740/3

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.)

सेजबहार में सरकारी जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा

मुख्यमंत्री जनदर्शन में ग्रामीणों ने की थी शिकायत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करने और उनकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ऐसे प्रकरणों पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू की है। आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सेजबहार में ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन पर माना के बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने और जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री करने की शिकायत स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में की थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को श्री साय ने गंभीरता से लिया और इसकी जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर को दिए थे।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम

और उनके अमले को सौंपा था। राजस्व अमले द्वारा की गई जांच के बाद सेजबहार में मुख्य सड़क से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया। इस जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्के निर्माण जैसे दुकान आदि भी बना लिए थे। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था।

आज एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, तहसीलदार श्री पवन कोसमा और अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती तुलसी राठौर ने राजस्व अमले के साथ पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के दुकाननुमा निर्माण को तोड़ दिया है। इसके साथ ही लगभग पांच-छह लोगों द्वारा कुछ जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर की गई तार फेसिंग को भी हटा दिया गया है।

अब इस जमीन से बेजाकब्जा हट जाने से किसानों को भी अपने खेतों तक जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा और सरकारी जमीन की सुरक्षा भी हो जाएगी। किसान चालू मानसून मौसम में खेतों में फसलों की बोआई आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपनी कास्तकारी जमीन में आने-जाने के लिए झगड़-लड़ाई मारपीट से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए सेजबहार गांव के निवासियों श्री शारदा राम साहू, श्री कामता प्रसाद साहू, श्री ललित साहू, श्री खेलन साहू, श्री दीनदयाल रात्रे, श्री दल्लू यादव श्री संतोष बघेल आदि ने मुख्यमंत्री श्री साय और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सभी गांव वासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महासमुन्द

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक- 4 (द्वितीय बार)

क्रमांक / 04 / एस.ए.सी./ग्रा.यां.से./2024-25 महासमुन्द, दिनांक 28/06/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू.) में
1	2	3
1	मिशन वात्सल्य अन्तर्गत चाईल्ड हेल्प लाईन कार्यालय में फर्नीचर एवं अन्य कार्य (Refurbishment cost, Working cubicles, Minor civil/electrical work etc.) पुराना कलेक्टोरेट परिसर, महासमुन्द	2.76 लाख
2	अतिरिक्त कक्ष निर्माण प्राथमिक शाला एवं (7.84) लघु मरम्मत चबूतरा जीर्णोद्वार कार्य (0.90) बेल्डीह वि.ख. पिथौरा	8.74 लाख
3	शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी में लघु मरम्मत कार्य वि.ख. पिथौरा (विद्युतीकरण सहित)	2.07 लाख

(टीप:- उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 08/07/2024)

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारियां विभागीय वेबसाईड https://res.cg.gov.in में दिनांक 28/06/2024 से डाउनलोड की जा सकती है।

जी-242500732/4

कार्यपालन अभियंता

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

एन.आई.टी.क्रमांक/01/आ.वि./ निर्माण/2024-25 कांकेर, दिनांक 01/07/2024

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना
(द्वितीय सूचना)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से निम्नांकित कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर, (सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत 'सी' श्रेणी एवं इसमें ऊपर श्रेणी के ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा भवन दर अनुसूची जो 01.01.2015 से प्रभावशील एवं अद्यतन संशोधन सहित एस.ओ.आर. पद्धति के तहत ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह (वर्षा काल सहित) होगी।

1- ई निविदा प्रारंभ तिथि - 01.07.2024
2- ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 16.07.2024
3- निविदा प्रपत्र की चालान एवं अमानत राशि (एफ.डी.आर.) प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि (स्पीड पोस्ट से) - 22.07.2024
4-निविदा खोलने की तिथि - 24.07.2024

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम / स्थान का नाम	निविदा की राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू. में)	अमानत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	155489	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मरकाटोला वि.ख. नरहरपुर भवन निर्माण कार्य (मय सेनेटरी फिटिंग व वाटर सप्लाई, सेप्टिक टैंक, बोर खनन, सम्पवेल व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य सहित)	111.51	3000.00	0.84

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट - https://eproc.cgstate.gov.in पर में देखे जा सकते है।

जी-242500761/6

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, कांकेर

बहुपक्षीय संबंध की ओर भारत की विदेश नीति

डॉ. आरके पटनायक

भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इसी के साथ एक ऐसा मोड़ आया है, जहां नेहरू युग में स्थापित मान्यताओं को चुनौती मिल रही है, जो साढ़े सात दशक के गणराज्य की यात्रा में सशक्त हुई हैं। गाजा में जनसंहार की आरोपी इस्राइल की नेतन्याहू सरकार से बढ़ती निकटता में यह परिवर्तन सबसे अधिक परिलक्षित हो रहा है। इस बड़े नीतिगत बदलाव को लेकर भारत में सर्वसम्मति नहीं है। विदेश नीति, भू-राजनीति और भू-आर्थिक मामलों में सर्वसम्मति की आवश्यकता कम ही महसूस की जाती है क्योंकि देश में ये गर्मागर्म बहस के विषय नहीं होते। एक सामान्य नागरिक या छात्र आम तौर पर इनके बारे में गहराई से नहीं सोचता। फिर भी बदलाव के महत्व को रेखांकित की आवश्यकता है क्योंकि इस पर सहमति या चर्चा का अभाव है। यह बदलाव वैश्विक मामलों के एक कठिन दौर में घटित हो रहा है। बीते 30 मई को जारी रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) में भू-राजनीतिक तनावों के गहरे होने, भू-आर्थिक बिखराव बढ़ने तथा वैश्वीकरण के पीछे हटने की स्थिति पर जोर दिया गया था। इस रिपोर्ट में 'भू-राजनीति' और 'भू-आर्थिकी' का उल्लेख 16 बार किया गया है। इससे इंगित होता है कि अर्थशास्त्र राजनीति से बहुत गहरे तौर पर प्रभावित हो रही है। इससे पता चलता है कि व्यापार, पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा बाजार, तेल के दाम, वैश्विक वित्तीय बाजार, मुद्रास्फीति आदि इस तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं कि वैश्वीकरण के सिद्धांतों से पीछे हटने से नयी एवं गंभीर आर्थिक चुनौतियां पैदा होंगी। ये चुनौतियां ऐसे दौर में आ रही हैं, जब दुनिया तनावों से जूझ रही है और सीमाओं के बंद होने, राष्ट्रीय एजेंडा का प्रभाव बढ़ने और मजबूत राष्ट्र-राज्य की प्राथमिकताएं जैसे तत्वों के वैश्वीकरण एवं बहुपक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने की आशंकाएं गहरी होती जा रही हैं। कुछ दिन पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने रेखांकित किया है कि व्यापार और निवेश का प्रवाह भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 और 2023 के बीच व्यापारिक तनाव के कारण अमेरिकी आयात में चीन का हिस्सा आठ प्रतिशत तथा चीन के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग चार प्रतिशत घटा है। यूक्रेन युद्ध तथा रूस पर पाबंदी की वजह से रूस और पश्चिम का सीधा व्यापार ध्वस्त हो चुका है। भू-राजनीतिक तनाव नयी बात नहीं है। अतीत में भी इसके असर विदेश व्यापार, पूंजी प्रवाह, मुद्रा प्रवाह और श्रम प्रवासन में देखे गये हैं। सोवियत संघ के पतन, नयी आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उत्थान, यूरोपीय संघ के गठन, सर्वशक्तिमान देश के रूप में अमेरिका का उदय तथा इस्राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष से हाल में पैदा हुए नये सवाल वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के कारण रहे हैं या बन रहे हैं। ऐसे प्रभाव अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन रहे हैं। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ऐसी स्थिति में जा रही है, जहां विकास और कल्याण संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च के बजाय रक्षा के मद में अधिक खर्च होगा। वर्ष 1990 में एडवर्ड लटवाक ने 'भू-अर्थव्यवस्था' शब्द-युग्म का पहली बार प्रयोग किया था। उनका कहना था कि शीत युद्ध की वैचारिक शत्रुता का स्थान विश्व भर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने लिया है, जहां व्यापार एवं वित्त सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। भू-अर्थव्यवस्था ज्ञान की एक शाखा के रूप में भू-राजनीति से निकली है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध राजनीति संबंधों से निर्देशित होते हैं। साल 1894 में ई कॉबहम ब्रीवर ने उपनिवेशों के संदर्भ में कहा था कि 'व्यापार झंडे का अनुसरण करता है और झंडा व्यापार का।' अब इसका उपयोग राजनीति और अर्थव्यवस्था के सह-प्रवाह को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। फिर भी, कुछ लोग कह सकते हैं, औपनिवेशीकरण की स्थिति बदली नहीं है क्योंकि वैश्विक व्यापार नयी औपनिवेशिक शक्ति है, जिसमें भारत में एक हिस्सा चाहता है। ब्रिक्स देशों में चीन एक नयी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चीन ने भू-राजनीति में भी अपने लिए जगह बनायी है। चीनी मुद्रा रेनमिंबी को मुद्रा कोष द्वारा मुद्रा बास्केट में शामिल करना इसे इंगित करता है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 ट्रिलियन डॉलर (अप्रैल 2024) है, जो विश्व व्यवस्था में उसकी बढ़ती वित्तीय शक्ति का परिचायक है। कच्चे तेल के भंडार (भू-आर्थिक क्षमता) और शक्तिशाली सेना (भू-राजनीतिक क्षमता) के साथ भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील है।

नये भारत में बदलाव के कानून

ललित गर्ग

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे।

अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए नए कानून लाने एवं उन्हें लागे करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से

कानूनों को बनाया गया है।

इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रयास किये गये हैं।

ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि वे गरीबों को न्याय दिलाने में असमानता के द्योतक थे। उन कानूनों का इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ही ज्यादा भुगतना पड़ता था। औपनिवेशिक युग के निर्मम या गरीब विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। अब इन नये तीन कानूनों ने ब्रिटिश काल के तीन कानूनों की जगह ले ली है, इसका एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे अपने यहां संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे एवं प्रभावी कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है, इससे जुड़ी खबरों का सामने आना भी सुखद है। सक्षम और सहयोगी पुलिस नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत में कारगर होगी।

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध की जांच-पड़ताल को आधुनिक तकनीक के जरिये न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना भी अनिवार्य है ताकि अपराधी संदेह का लाभ न उठा सकें। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में बढ़ेगा। नये कानून के अनुसार मौत की सजा पाये अपराधी को खुद ही दया याचिका दायर करनी होगी, कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा न कर सकेगा। निश्चित ही जहां सरकार वर्तमान संदर्भ के अनुरूप कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है वहीं उसे कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने एवं पुलिस-व्यवस्था को सुधारने एवं सक्षम बनाने के लिये साधन-सुविधाओं को सुलभ कराने के लिये तत्पर होना होगा। नये कानून एवं नयी आधुनिक अदालते कल के भारत को और मजबूत करेगी। नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने में इनकी सर्वाधिक सार्थक भूमिका होगी। सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में न्याय-प्रक्रिया को संचालित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है।

नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान होगा। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। उपर्युक्त सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्याय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की दरकार को महसूस करते हुए वैसी व्यवस्थाएं की गयी है। लेकिन यह सुधार न सिर्फ न्यायपलिका के बाहर से बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी होने चाहिये। ताकि किसी भी प्रकार के नवाचार को लागू करने में न्यायपालिका की स्वायत्तता बाधा न बन सकें। न्यायिक व्यवस्था में न्याय देने में विलंब न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, अतः न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि दिखना भी चाहिये। नये कानूनों एवं नयी कानूनी व्यवस्थाओं से ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो नये भारत की ओर गति को दर्शा रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

हंसोपनिषद् ॥ (भाग-4)

यह उपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हैं। इसमें कुल 21 मन्त्र हैं। ऋषि गौतम एवं सनत्कुमार के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद् प्रकट हुई है। इसमें ऋषि गौतम द्वारा ब्रह्मविद्या की बात पूछे जाने पर सनत्कुमार जी ने वह प्रसंग सुनाया, जो महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया था। यह बड़ा ही गुह्य ज्ञान है, जिसे महादेव ने शान्त (मनोनिग्रह युक्त), दान्त (इन्द्रियनिग्रह युक्त) और गुरुभक्त को ही देने की बात कही है। वह हंस (जीवात्मा) सभी शरीरों में उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे काष्ठ में अग्नि और तिलों में तेल। उसकी प्राप्ति के लिए षट्चक्र वेधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अष्टदल कमल से उसकी वृत्तियों का साम्य बताते हुए शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्म %का स्वरूप वर्णित किया है। यही हंस भी कहा जाता है। इसके ध्यान से नाद की उत्पत्ति कही गई है। जिसकी अनेक रूपों में अनुभूति होती है। इसी की चरमावस्था में परब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यही अवस्था समाधि की स्थिति है। इसी स्थिति में शुद्ध-बुद्ध, नित्य, निरञ्जन, शान्त स्वरूप परब्रह्म के प्रकाशित होने का वेदानुवचन भी प्रसिद्ध है। ऋषि गौतम ने (सनत्कुमार से) प्रश्न किया हे भगवन्! आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के विशारद हैं। आप यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सनत्कुमार ने कहा-हे गौतम! महादेव जी ने समस्त धर्मों (उपनिषदों) के मतों को विचार कर श्री पार्वती जी के प्रति जो भी कहा (व्याख्यान दिया) उसे तुम मुझसे सुनो। एक कोश के समान है। हंस (परम आत्मा) की आकृति (स्थिति) का वर्णन भोग एवं मोक्षफल प्रदाता है। जो गुरुभक्त सदैव हंस-हंस (सोऽहम्, सोऽहम्) का ध्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय तथा शान्त मनःस्थिति (इन्द्रियों) वाला हो, उसके समक्ष हंस-परमहंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए।(

(क्रमशः)

स्वामी विवेकानन्द अध्यात्म-विज्ञान के समन्वयक थे

ललित गर्ग

स्वामी विवेकानन्द की कीर्ति युग-युगों तक जीवंत रहेगी, क्योंकि उनका मानवहितकारी चिन्तन एवं कर्म कालजयी हैं, वे एक प्रकाश-स्तंभ हैं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, युगीन समस्याओं के समाधायक, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक एवं आध्यात्मिक सोच के साथ पूरी दुनिया को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने वाले एक महामनीषी युगपुरुष थे। जिन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए थे। सचमुच! वह कर्मवीर कर्म करते-करते कृतकाम हो गया। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, भारत को अध्यात्म के साथ विज्ञानमय बनाया, वे अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वयक थे। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किसके लिये किया- इन सारे प्रश्नों का उत्तर तलाशना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में उनके प्रयासों एवं प्रस्तुति के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीव स्वयं परमात्मा का ही एक अवतार हैं। इसलिए मानव जाति की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है।

भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त संत एवं भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा पुरुष के रूप में माना जाता हैं। वे अध्यात्म की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने वाले योग साधक थे तो व्यवहार में जीने वाले गुरु भी थे। वे प्रज्ञा के पारगामी थे तो विनम्रता की बेमिशाल नजीर भी थे। वे करुणा के सागर थे तो प्रखर समाज सुधारक भी थे। उनमें वक्तृता थी तो शालीनता भी। कृशता थी तो तेजस्विता भी। आभिजात्य मुस्कानों के निधान, अतीन्द्रिय चेतना के धनी, प्रकृति में निहित गूढ़ रहस्यों को अनावृत्त करने में सतत् संलग्न, समर्पण और पुरुषार्थ की मशाल, सादगी और सरलता से ओतप्रोत, स्वामी विवेकानन्द का समग्र जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला था, एक मिशन था, भारतीय संस्कृति के अभ्युदय का अनुष्ठान था।

स्वामी विवेकानन्द बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदान्त के सिद्धान्तों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धान्त का जो आधार उन्होंने दिया उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूँढा जा सके। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा संन्यासी चाहिये जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जायें।

विश्व मंच पर चीन का पंचशील राग क्यों ?

राजेश बादल

चीन के सुर बदल रहे हैं। सुर बदलने का रहस्य अभी पर्दे में है। 70 साल बाद उसे अचानक पंचशील की याद आई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत-चीन-म्यांमार के बीच पंचशील समझौते की सत्तरवीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम में फरमाया कि इन वर्षों में बार-बार साबित हुआ है कि पंचशील सिद्धांत शांति और विकास के लिए सबकी जरूरत बन गए हैं। आश्चर्य है कि पंचशील की नींव डालने वाले जवाहरलाल नेहरू का चीन ने कोई जिक्र ही नहीं किया।

चीन का दावा है कि भारत को भी इसमें बुलाया गया था, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। आपको याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई जब सीमा विवाद नहीं सुलझा सके तो उन्होंने 1954 में पांच सिद्धांतों पर आपसी सहमति बनाई थी। चीन और म्यांमार के बीच भी ऐसी ही सहमति बनी थी। यह सिद्धांत थे, एक-दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक-दूसरे के प्रति आक्रामक कार्रवाई नहीं होना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर अमल करना।

पंचशील के इन सिद्धांतों को बाद में गुटनिरपेक्ष देशों ने भी अपना सूत्र वाक्य माना। नेहरू के पांच सिद्धांतों वाले शील पर पक्की मुहर लग गई। इस बीच कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पंचशील को लोकप्रियता मिली और अरसे तक समूची दुनिया में ठीक-ठाक सी शांति बनी रही। हिंदुस्तान और चीन के बीच यह समझौता आठ साल के लिए हुआ था। यानी 1962 तक अनुबंध चलता रहा। जैसे ही समझौते की उमर पूरी हुई,

चीन ने भारत पर हमला कर दिया। शायद वह इंतजार ही कर रहा था कि करार खत्म हो और वह पंचशील की धज्जियां उड़ा दे। लेकिन हकीकत तो यह है कि 1959 आते-आते चीन के सुर बदलने लगे थे। उसने समझौते को एकतरफा चुपचाप तोड़ना शुरू कर दिया था। वह 1959 से 1962 के बीच सीमा पर सड़कें बनाता रहा। अक्साई चिन में तो उसने 1957 में ही सड़क बना ली थी। यानी उसकी नीयत में खोट था। भारत उसे नहीं पढ़ सका था।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार संपादक राजेंद्र माथुर ने लिखा था कि पंचशील समझौते के चार-पांच साल बाद से ही भारत के प्रति चीन का रवैया सख्त और बदनीयत वाला होता गया। तिब्बत में बगावत के बाद उसने भारत को जो चिट्ठियां लिखीं, वे इतनी जहरीली और घमंड भरी थीं कि दोस्त तो क्या, दुश्मन देश भी एक-दूसरे को ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखा करते। शायद तिब्बत में बगावत के बाद चीन ने तय कर लिया था कि वह अब हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देगा। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन ने भारत की दोस्ती की कद्र नहीं की। वह शीत युद्ध की भाषा का उपयोग कर रहा है, जो हजारों साल की संस्कृति वाले देश को शोभा नहीं देता। उसने आरोप लगाया कि भारत ने दलाई लामा को नजरबंद कर रखा है और तिब्बत में वह अंग्रेजों की प्रसारवादी नीति पर अमल कर रहा है। कलिम्पोंग को अड्डा बनाकर उसने विद्रोह भड़काया है। एक बड़े देश की ताकत का घमंड चीन में आ गया है। तब से लेकर आज तक चीन का यही रवैया चला आ रहा है।

चीन के सुर बदलने के पीछे की मंशा क्या है, इसकी पड़ताल आवश्यक है, क्योंकि शी जिनपिंग वही हैं जो भारत को हालिया वर्षों में अनेक बार धमका चुके हैं। भारत यात्रा में वे चुप रहते हैं, लेकिन यहां से नेपाल पहुंचते ही चीनी संप्रभुता पर कुचल कर रख देने की चेतावनी दे डालते हैं। उनका गुस्सा ताइवान और तिब्बत पर भारत की नीति के बारे में था। शी जिनपिंग आखिरी सांस तक चीन के चक्रवर्ती बने रहना चाहते हैं। वहां वे क्रूर तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं, आलोचकों को कुचलते हैं, छोटे देशों की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखते और उन्हें ऋण जाल में उलझाते हैं।

अपने इस चरित्र को लेकर कुख्यात शी जिनपिंग अचानक जब विश्व मंच पर शांति और पंचशील की बातें करने लगते हैं, तो ताज्जुब होता है। वे नेहरू को याद नहीं करते लेकिन उनका पंचशील-गीत गाते हैं। उसी पंचशील की, जिसकी उनका देश 1962 में खिल्ली उड़ा चुका है। उसी पंचशील का भारत के पड़ोसियों ने भरपूर समर्थन किया था। पर जब चीन ने आक्रमण किया तो उन्हें भी चोट लगी थी। इसलिए 2024 में जब चीन इसी पंचशील के आधार पर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का समर्थन जुटाने की कवायद करता है तो हिंदुस्तान के लिए उसका रुख रहस्यमय हो जाता है।

पंचशील पर लौटने के पीछे चीनी मंशा वैश्विक मंच पर हो रहे ध्रुवीकरण में अपनी चौधराहट साबित करने की भी हो सकती है। अभी तक उसका चेहरा एक कुटिल, चालबाज और धूर्तता का रहा है, जो छोटे देशों को कर्ज या उनके नेताओं को घूस देकर जाल में फांसता है। लेकिन अब वह इस चेहरे पर एक और शांति का मुखौटा लगाना चाहता है। यह मुखौटा लगाने से अगर पश्चिम और यूरोप के देशों से मुकाबले के लिए एशियाई और अफ्रीकी मुल्क उसके झंडे तले एकत्रित होते हैं तो उसका मुखौटा लगाना सार्थक हो जाता है।

इसके अलावा यह मुखौटा रूस और भारत के लिए एक कूटनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन जाते हैं, उत्तर कोरिया जाते हैं। शी जिनपिंग यूरोप जाते हैं। यह अलग बात है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अनमने भाव से उनको महत्व दिया। फिर भी रूस-यूक्रेन जंग और शेष विश्व की आंतरिक परिस्थितियों के चलते एक अलग ढंग से ध्रुवीकरण के संकेत तो मिल ही रहे हैं। भारत को अब उसके नए पैंतरे से सतर्क रहना होगा।

आज का इतिहास

1928 एलेफ्थेरिओस वेणिजेलोस पांचवी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए।
1943 पोलिश सरकार के निर्वासन के प्रधानमंत्री व्लाडिसलाव सिकोरस्की को ले जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उनकी और पंद्रह अन्य की मौत हो गई, जिससे कई षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए।
1945 ब्राजील के क्रूजर बहिया गलती से अपने ही दल के एक चालक दल द्वारा डूब गया, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और बचे-खुचे इंशोर-संक्रमित पानी में फंसे।
1946 अंकारा विश्वविद्यालय तुर्की में स्थापित किया गया।
1946 द्वीप समूह फिलीपीन को अमरिका से स्वतंत्रता मिली।
1950 संयुक्त राज्य अमेरिका के कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार रेडियो फ्री यूरोप ने चेकोस्लोवाकिया में अपना पहला प्रसारण किया।
1951 विलियम शॉकले ने जंक्शन ट्रांजिस्टर के आविष्कार की घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने, जॉन बार्डीन, और वाल्टर हाउस्टर ब्रेटन ने 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता।
1965 पहला वार्षिक अनुस्मारक, संयुक्त राज्य अमेरिका के शुरुआती एलजीबीटी प्रदर्शनों में से एक, होमोफाइल संगठनों द्वारा आयोजित शुरुआती पिकेट्स की एक श्रृंखला, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल में हुई।
1976 इजरायल के रक्षा बलों ने एयर फ्रांस फ्लाइट 139 पर अपहर्ताओं द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त करने के लिए युगांडा के एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छापा मारा।
1996 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन पुनः चार वर्ष हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
1997 नासा का पाथ फाइंडर स्पेस प्रोब मंगल की सतह पर उतरा। मार्स पाथ फाइंडर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जो 1997 में मंगल ग्रह पर एक मोबाइल जांच के साथ बेस स्टेशन पर उतरा था। इसमें एक लैंडर शामिल था जिसे कार्ल सगन मेमोरियल स्टेशन और एक हल्के पहियों वाले रोबोटिक मार्स रोवर के रूप में नाम दिया गया था जिसे सोजॉर्नर नाम दिया गया था।
1997 अमेरिकी यान 'सोजर्नर' मंगल ग्रह पर पहुँचा।
1998 जापान ने मंगल पर नोज़ोमी जांच शुरू की और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में एक अंतरिक्ष की खोज करने वाले राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया। नोजोमी को एक मंगल ग्रह की वायुमंडलीय जांच के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। लेकिन यह विद्युत विफलताओं के कारण मंगल की कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा। ऑपरेशन 31 दिसंबर 2003 को समाप्त हो गया था
1998 ब्रिटेन के एक पावरबोट 'द केवल एंड वायरलेस एडवेंचर' ने 74 दिन 20 घंटे व 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे शीघ्र विश्व भ्रमण का रिकार्ड तोड़ा।
2003 पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए हमले में 44 मारे गये।
2005 नासा अंतरिक्ष जांच डीप इम्पैक्ट ने धूमकेतु टेम्पेल 1 के नाभिक को प्रभावित किया, इसके आंतरिक भाग से मलबे की खुदाई की ताकि इसकी स्थिति का अध्ययन किया जा सके।

महाशक्ति के दर्जे के लिए एक नया एजेंडा

श्याम सरन

नई सरकार का गठन इस बात का अवसर है कि देश की आर्थिक रणनीतियों की समीक्षा की जाए। सालाना बजट जल्दी ही सदन में पेश किया जाएगा। बजट में ऐसी आर्थिक नीति पेश की जानी चाहिए जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें, जो भारत की आजादी की सौवीं वर्षगांठ का वर्ष है।

इस रणनीति को निर्धारित करने के लिए कुछ सीमाओं की आवश्यकता है। भारत चीन की वृद्धि के तौर तरीकों का अनुकरण नहीं कर सकता है। चीन ने वृद्धि के लिए संसाधन और ऊर्जा आधारित रुख अपनाया। उसने विकसित देशों के औद्योगीकरण के मॉडल को अपनाया। चीन के मॉडल का अनुकरण भारत नहीं कर सकता है। दुनिया में एक और चीन की गुंजाइश नहीं है। चीन का मॉडल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा पारिस्थितिकी संबंधी टिकाऊपन की जरूरी मांगों के साथ तालमेल वाला भी नहीं है।

चीन शायद इस वर्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और अब इसमें गिरावट आएगी। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो भारत का उत्सर्जन भी बढ़ेगा और हम पर यह अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि हम उत्सर्जन में कमी करें। ऐसा इसलिए कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन संबंधी कदम तेज होंगे।

अपनी वृद्धि संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए भारत को ऐसी आर्थिक रणनीति अपनानी होगी जो मौजूदा जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवस्था से नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा माध्यमों पर आधारित व्यवस्था में तेजी से रूपांतरण कर सके। भारत पहले ही ऊर्जा में बदलाव की प्रक्रिया अपना चुका है लेकिन उसे इससे भी तेज गति से यह करना होगा।

भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसी दशक में वह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन सकता है। परंतु यह उसके भू-राजनीतिक प्रभाव में तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपनी आर्थिक संबद्धता नहीं बढ़ाते। लक्ष्य होना चाहिए देश के विदेश व्यापार में इजाफा ताकि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी ताकत बन सकें। भारत की वैश्विक आर्थिक छाप बहुत तगड़ी नहीं है। दुनिया के निर्यात में अभी भारत की हिस्सेदारी 1.8 फीसदी है और वह 18वें स्थान पर है। वैश्विक आयात में हम 2.8 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में नौवें स्थान पर हैं। भारत को अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की संरक्षणवादी नीतियों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उसे मौजूदा वैश्विक व्यापार की दो विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए।

पहली, इस व्यापार का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं के तहत व्यवस्थित है। ऐसे में यह बात भारत के हित में है कि वह ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बने, खासतौर पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) का। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम जल्दी ही

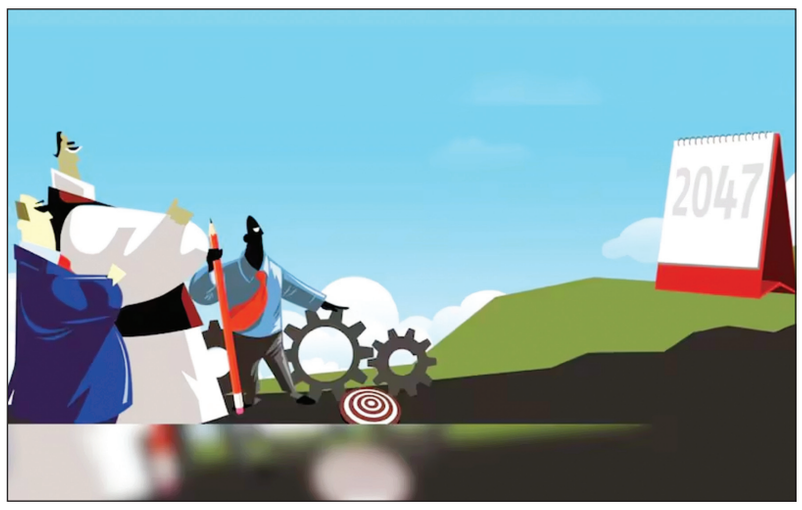

कांप्रेहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) में शामिल हों। ये दोनों व्यापार समझौते एशिया केंद्रित हैं और आने वाले वर्षों में विश्व व्यापार में एशिया ही सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। इन समझौतों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए और इसके लिए उचित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कुछ विकसित देश ऐसा कर चुके हैं।

भारत को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) में शामिल होने के आवेदन को नए सिरे से प्रस्तुत करना चाहिए। यह कोई कारोबारी व्यवस्था नहीं बल्कि एक मंच है जहां बेहतरीन व्यवहार साझा किए जाते हैं और जो नीतिगत सुसंगतता, सुविधा और निवेश को बढ़ावा देने तथा बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करने का काम करता है। फिलहाल विश्व व्यापार का करीब 70 फीसदी क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिये होता है। अगर भारत को वैश्विक कारोबारी शक्ति बनना है तो उसे इनका हिस्सा बनना होगा। उच्च सीमा शुल्क वाली व्यवस्था इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी की राह में बाधा है। वर्ष 2014-15 से भारत के सीमा शुल्क में नियमित इजाफा हुआ है।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और जाने माने व्यापार अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे एक आलेख में कहा कि 2014-15 में जहां उच्च आयात शुल्क की शुरुआत हुई वहीं असली बदलाव 2018-19 में आया जब सभी शुल्कों में 42.3 फीसदी का इजाफा हुआ। सीमा शुल्क भी औसतन 13.7 फीसदी से बढ़कर 17.7 फीसदी हो गया। उन्होंने कहा, 'यह उदारीकरण से संरक्षणवाद की ओर स्पष्ट बदलाव था।'

अगर भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे इस स्थिति को पलटना होगा। आगामी बजट में यह बदलाव नजर आना चाहिए। घरेलू मूल्यवर्धन अधिक ढांचागत सुधारों पर केंद्रित होना चाहिए। मसलन अधोसंरचना में सुधार, नियामकीय और नीतिगत सुधार तथा तकनीकी नवाचार। शुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का आलसी किस्म का उपाय है। दुनिया में किसी भी देश ने बिना जीवंत विनिर्माण के अहम आर्थिक प्रगति नहीं की है। भारत जैसे देश में जहां आबादी अधिक है और तेजी से बढ़ रही है तथा जहां युवा बहुत हैं, वहां श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। औद्योगीकरण के आरंभिक दौर में असंगठित क्षेत्र छोटे और मझोले उपक्रम ही रोजगार का प्रमुख साधन रहेंगे।

अब जबकि आधुनिक और पूंजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक बड़ा सुधार है लेकिन इसके प्रावधान और अनुपालन प्रक्रियाओं की लागत छोटे और मझोले उपक्रमों पर भारी पड़ती है। जीएसटी की प्रक्रियाओं को सहज बनाने तथा वर्तमान 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले लोगों के लिए रियायत की सीमा बढ़ाने की जरूरत है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से यह तकनीक तथा पूंजी गहन उद्योगों को बढ़ावा देती है लेकिन इससे बहुत अधिक रोजगार नहीं तैयार होते। जो दुर्लभ संसाधन अभी इस योजना के लिए आरक्षित हैं उनका इस्तेमाल छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए बेहतर हालात बनाने में किया जा सकता है। यह काम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है।

औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार की कोशिशों के बावजूद देश की 50 फीसदी आर्थिक गतिविधियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश का 80 फीसदी से अधिक गैर कृषि रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को खारिज करने के बजाय उसे जीवंत वृद्धि और रोजगार का संभावित स्रोत मानना चाहिए। इसे आधुनिक होती अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए।

एक नए राजनीतिक प्रतिष्ठान के पास यह अवसर होता है कि वह आर्थिक मोर्चे पर नए विचार सामने रखे, पुराने अनुमानों पर सवाल खड़े करे और नए रवैयों की पड़ताल करे। यह बहस सरकारी तंत्र से आगे बढ़कर व्यापक नागरिक समाज तक पहुंचनी चाहिए। आज हम जो दिशा तय करेंगे वही आने वाले समय में देश के भाग्य का निर्धारण करेगी।

योगी का कद घटाने की कोशिशों के चलते यूपी की सीटें घटीं!

निरंकार सिंह

लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें कम मिलने के कारण भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल प्रदेश और देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से उनके मंत्रिमंडल के ही कुछ लोग काफी परेशान हैं। इन मंत्रियों की मुख्यमंत्री बनने की लालसा भी हिलोरें मार रही है। जाने-अनजाने में कुछ केंद्रीय नेताओं का भी इन्हें संरक्षण मिल रहा था।ये लोग नहीं चाहते थे कि योगी की लोकप्रियता बढ़े। इसलिए लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जिताने और बढ़ाने में इनकी कोई विशेष सक्रियता भी दिखाई नहीं पड़ी। अब पार्टी संगठन एक टास्क फोर्स बनाकर इसके कारणों की छानबीन कर रहा है।

प्रदेश में भाजपा की सीटें घटने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, दो बार लगातार चुनाव जीतने वाले सांसदों का अपने-अपने क्षेत्र में भाजपा के कार्यकताओं के साथ-साथ जनता से संपर्क टूट गया था। यदि आप सांसद या विधायक हैं तो आपको अपने क्षेत्र का बराबर दौरा करना चाहिए। लोगों की समस्याएं जाननी चाहिए। ये लोग मोदी और योगी के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीदें लगाए बैठे थे, इसलिए अपने क्षेत्रों में जनता से संपर्क साधने की जरूरत नहीं समझी। दूसरा बड़ा कारण, भाजपा प्रदेश और जिला संगठन भी जनता से दूर हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कितने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए कितनी बार दौरा किया, इसका कोई ब्यौरा पार्टी संगठन के पास नहीं है। भाजपा को सबसे ज्यादा हैरानी अमेठी, फैजाबाद (अयोध्या वाली सीट), बलिया और सुलतानपुर जैसी सीटों पर हार से है। इन सीटों को भाजपा के लिए मजबूत माना जाता था। अमेठी में स्मृति ईरानी की कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता से हार ने पूरे नैरेटिव को चोट पहुंचाई है। इसके अलावा अयोध्या की हार भी कान खड़े करने वाली है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी चुनाव हार गईं, जो लगातार जीतती रही हैं। फिर अयोध्या की हार ने तो पूरे नैरेटिव को ही चोट पहुंचाई है। अब पार्टी पूरे नैरेटिव को कैसे सेट करे और अपनी हार को कैसे पचाया जाए, इसकी तैयारी में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा को आरएसएस और उसके आनुषांगिक संगठनों से भी फीडबैक मिलेगा। संघ के लोगों से भी कहा गया है कि वे समीक्षा करके बताएं कि हार के क्या कारण रहे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में खराब छवि वाले कई सांसदों का टिकट काटने से परहेज किया। अधिक सीट जीतने पर योगी को हटाया जा सकता है, इस नैरेटिव का भी असर हुआ इसलिए उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें हासिल हुई हैं। इसको लेकर भाजपा पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं।

स्पेशल पैकेज देने से पहले कुछ नए मापदंड तय हो

कमलेश पांडे

अपने देश में कई राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की मांग केंद्र सरकार से करते आये हैं, लेकिन यह दर्जा या सुविधा इन्हें कबतक मिलेगी, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हां, इतना जरूर है कि बिहार, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य समय-समय पर अपने लिए विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की मांग करते रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है।

बताया जाता है कि पिछड़ेपन, ज्यादा आदिवासी आबादी और कम राजस्व का हवाला देकर उपरोक्त राज्य लंबे समय से अपने लिए विशेष दर्जे (स्पेशल स्टेटस) की मांग करते आये हैं। हालांकि 14वां वित्त आयोग केंद्र सरकार को काफी पहले ही यह सलाह दे चुका है कि इस कैटिगरी में अब किसी राज्य को नहीं जोड़ा जाए। यही वजह है कि कुछ राज्यों ने अब अपने सुर बदल लिए हैं और विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज की मांग करने लगे हैं।

समझा जाता है कि भले ही पिछली कार्यकाल तक बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार 14वें वित्त आयोग का हवाला देकर इस मांग को ठुकरा रही थी, लेकिन अब वह आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी और बिहार में काबिज जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है, इसलिए अब मोदी सरकार भी अपने पुराने रूख पर कायम रह पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हां, इस मांग में इतना बदलाव जरूर दृष्टिगोचर हो रहा है कि अब बिहार और आंध्रप्रदेश जैसे राज्य विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज की मांग करने लगे हैं, जिससे इंकार करने की कोई वजह भी किसी नहीं दिखती।

दरअसल, विशेष राज्य का दर्जा देने का किस्सा आजादी के बाद के दूसरे दशक में शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार ने महसूस किया कि विकास की दौड़ में पिछड़ रहे

कुछ राज्यों को सहारा देना होगा। इसके दृष्टिगत योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल के फार्मूले पर विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल कैटिगरी स्टेटस की व्यवस्था की गई। जिसमें पहाड़ी राज्यों, ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्यों, सीमावर्ती राज्यों, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के लिहाज से पिछड़े राज्यों और ऐसे राज्यों पर विचार किया गया, जो अपने लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था न कर पाते हों।

इस दृष्टिकोण से प्रारंभ में जम्मू-कश्मीर, असम और नागालैंड को दर्जा मिला। यद्यपि बाद में इसकी सूची बढ़ती गई और अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सहित 11 राज्य इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। बताया जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा वित्तीय मदद मिलती है। ऐसे राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत फंड केंद्र सरकार देती है और 10 प्रतिशत फंड की राज्य सरकार को देनी होती है, यानी 90-10 का अनुपात। जबकि दूसरे राज्यों में यह अनुपात 60-40 का होता है।

वहीं, विशेष दर्जे वाले राज्यों को कुछ योजनाओं में अलग से भी मदद मिलती है। यही वजह है कि 14वें वित्त आयोग (फाइनैंस कमीशन) ने विशेष राज्य का दर्जा वाली सूची में अब और अधिक राज्यों को न जोड़ने की सलाह दी थी। हालांकि अब एनडीए गठबंधन के दबाव के मद्देनजर मोदी सरकार स्पेशल पैकेज के जरिए बीच का रास्ता निकाल सकती है। इसकी वजह ये है कि अब बिहार की जेडीयू ने अपने प्रस्ताव में स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज की बात कर इसका संकेत दे दिया है। वहीं, आंध्रप्रदेश की टीडीपी भी स्पेशल स्टेटस के बजाय स्पेशल पैकेज पर फोकस कर रही है, क्योंकि चुनावी वायदे को पूरे करने के लिए उसे जल्द ही बड़ी रकम की जरूरत है।

इधर, आर्थिक मामले के जानकारों का कहना है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के पैमाने पर बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की मांग जायज है। जबकि आंध्र प्रदेश पिछड़ा नहीं है। यह बात दीगर है कि आंध्रप्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व हैदराबाद से मिलता था और वह उसके हाथ से चला गया। इसलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत है। उधर, आंध्रप्रदेश के विभाजन से बना तेलंगाना राज्य को मदद की जरूरत ज्यादा है।

वहीं, बिहार के बारे में दलील दी जा रही है कि पिछले 3 दशकों से वहां का गवर्नेंस ठीक नहीं है। इसलिए जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगा, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए केंद्र सरकार भी पशोपेश में है। वह इस बात को समझ रही है कि यदि इन राज्यों को विशेष पैकेज के नाम पर मदद दे दी जाए तो उस पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड तेज रफ्तार से बढ़ रहा है।

वैसे भी कोई राज्य पिछड़ रहा हो तो उसकी मदद की जिम्मेदारी केंद्र की है, क्योंकि वह सबका अभिभावक है। हां, इतना जरूर है कि 21वीं सदी के अनुरूप इस आशय का वह एक नया मानक बनाये और उसी के तहत जरूरतमंद राज्यों की मदद करे। अन्यथा अन्य राज्यों में भी यह मांग उठेगी, जिससे केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि केंद्र में गठबंधन सरकार का युग वापस लौट चुका है और अब हर राज्य अपने संसदीय संख्याबल के हिसाब से केंद्र की बांहें मरोड़ने की तैयारी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिससे सचेत रहने की जरूरत है।

जीत दिलाने वाले खिलाड़ियों का टी-20 से संन्यास

राज कुमार

बेशक क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन अपने असाधारण प्रदर्शन के बल पर कुछ खिलाड़ी विशिष्ट पहचान बना लेते हैं। सुनील गावस्कर, कपिलदेव और सचिन तेंदुलकर को कभी भुलाया जा सकेगा क्या? टी-20 वर्ल्ड कप जीत में भारतीय टीम और परदे के पीछे के किरदारों की अहम भूमिका रही, लेकिन जो 'त्रयी' इस विश्व विजय के साथ विदा हुई, वह इसका मुख्य आधार रही। एक ने मार्गदर्शक और रणनीतिकार की भूमिका निभायी, तो बाकी दो ने मैदान पर करिश्मा दिखाया। तेरह साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को चौथा विश्व कप खिताब जीतने का मौका मिला। टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को 17 साल इंतजार करना पड़ा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस टी-20 वर्ल्ड कप में शुरू से ही टीम इंडिया ने जैसा प्रदर्शन किया, उसे खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था।

टीम इंडिया सात मैच जीत कर फाइनल में पहुंची। एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। दक्षिण अफ्रीका अपने सभी आठ मैच जीत कर पहली बार फाइनल में पहुंची। भारत को 176 रनों पर रोक कर दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह लक्ष्य का पीछा किया, उससे साबित हुआ कि वह वाकई बराबरी की टीम थी। मैच का पलड़ा 16वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका की ओर झुका रहा। उसे 24 गेंदों पर जीत के लिए 26 रन की जरूरत थी, जबकि कलासेन और मिलर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर थे। लेकिन अंतिम चार ओवरों में बाजी पलटते हुए टीम इंडिया ने सात रन से मैच जीत लिया।

डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हरा कर टीम इंडिया के फाइनल में प्रवेश करते ही चर्चा शुरू हो गयी थी कि वह अपने हेड कोच राहुल द्रविड़ को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ विदाई देना चाहेगी। साल 2021 से टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी निभा रहे द्रविड़ का कार्यकाल इस वर्ल्ड कप तक ही था। टी-20 वर्ल्ड कप की गुरु दक्षिणा द्रविड़ के लिए इसलिए भी खास है कि 2007 में उसी वेस्ट इंडीज की धरती पर वन डे वर्ल्ड कप में उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया पहले ही

दौर में हार गयी थी। सुनील गावस्कर के बाद तकनीकी रूप से भारत के सबसे मजबूत बल्लेबाज रहे द्रविड़ सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और जैक्स कालिस के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी और फिर 'अंडर-19' और 'इंडिया-ए' टीम के भी हेड कोच रह चुके द्रविड़ ने जीत के इस तोहफे के लिए टीम इंडिया और खासकर कप्तान रोहित शर्मा की जिन शब्दों में प्रशंसा की, उससे उनकी विनम्रता झलकती है- 'बेशक रोहित महान बल्लेबाज और कप्तान हैं, पर मैं उन्हें महान इंसान के रूप में याद रखूंगा और उसी रूप में उनके साथ रिश्ता रखूंगा।'

इस वर्ल्ड कप के साथ हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया से अलग होना तय था। टीम इंडिया द्वारा उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में वर्ल्ड कप जीत का तोहफा देने की उम्मीदें भी थीं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनते ही जिस तरह दोनों बड़े खिलाड़ियों ने टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। रोहित और विराट हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय पहचान ही बन गये। फाइनल में भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे विराट कोहली ने सबसे पहले टी-20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 'प्लेयर ऑफ द फाइनल' का पुरस्कार लेते हुए कोहली ने ऐलान किया कि यह उनका टीम इंडिया के लिए आखिरी टी-20 मैच था। टूर्नामेंट के पहले के मैचों में कुछ खास नहीं कर पाये कोहली ने फाइनल में 59 गेंदों पर 76 रन बनाये। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। साल 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप से शुरुआत कर लगातार नौ वर्ल्ड कप खेलने वाले रोहित ने इस टूर्नामेंट में लगातार विस्फोटक ओपनिंग दी। उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी का लोहा दूसरी टीमें भी मानती हैं। जीत के बाद भावुक होकर मैदान पर लेटने और मिट्टी को चूमनेवाले रोहित ने कहा- 'टी-20 से संन्यास के लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं हो सकता है। मैं पूरी संतुष्टि के साथ क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अलविदा कह रहा हूं।'

कमोबेश यही बात विराट कोहली ने कही कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना साकार होने के बाद विदाई का यही सही समय है। भारत में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं। उन्हें आगे आना चाहिए। रोहित और विराट के रिश्तों की गर्मजोशी भी मैदान पर दिखी। विराट को गले लगा कर रोहित की आंखों से आंसू छलक आये। रोहित और विराट के प्रशंसकों के लिए राहत की बात है कि ये दोनों वन डे और टेस्ट क्रिकेट के साथ-साथ आइपीएल भी खेलते रहेंगे। रोहित और विराट के टी-20 से संन्यास के कारणों को लेकर कुछ अटकलें भी हैं, जिनका सच शायद ही पता चले। बेशक आइपीएल और इस टी-20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बताता है कि 'जय-वीरू' जैसी यह जोड़ी आगे भी खेल सकती थी, लेकिन कहा जाता है कि संन्यास तब लेना चाहिए, जब लोग पूछें कि अरे अभी से, न कि तब जब लोग पूछने लगें कि अभी भी नहीं?

विदेशी निवेशकों के लिए भारत में चुनाव नतीजे के मायने

आकाश प्रकाश

मुझे अमेरिका में वैश्विक निवेशकों एवं दीर्घ अवधि के लिए पूंजी लगाने वाले दिग्गजों के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिला था। इनमें कई निवेशक और लंबे समय के लिए दांव लगाने वाले लोग अपने क्षेत्र के महारथी हैं। भारत में जब लोक सभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तब मैं अमेरिका में ही था। नतीजे आने के बाद वहां भारत को लेकर मैंने इन निवेशकों एवं धनकुबेरों के जो हाव-भाव देखे उनसे कई प्रमुख बातें सामने आईं। चुनाव नतीजे चकित करने वाले थे क्योंकि ये अनुमान या उम्मीद के अनुरूप नहीं थे, मगर इन्हें लेकर किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी। सभी यह सोचकर खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता संभालेंगे। इसका एक कारण यह था कि कांग्रेस का अर्थशास्त्र उनके गले नहीं उतर पाया। कुछ लोग गठबंधन सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत को लेकर जरूर सशंकित थे मगर ऐसे लोगों की संख्या कम थी। अधिकांश लोगों का यही कहना था कि भाजपा को मिलीं 240 सीटें कम तो नहीं मानी जा सकती, इसलिए यह गठबंधन मजबूती के साथ अपना पांच वर्ष का कार्यकाल आराम से पूरा कर लेगा। गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों के विचारों की अनदेखी नहीं होती है और देश की विविधता भी सटीक तरीके से प्रतिबिंबित हो पाती है। हालांकि, भूमि एवं श्रम सुधारों में देरी हो सकती है, मगर चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत तुर्किये या हंगरी बनने के जोखिम से काफी दूर है। इन चुनाव नतीजों से आर्थिक वृद्धि को लेकर हमारे पूर्वानुमान और एवं इसकी (वृद्धि) चाल में निरतंरता दोनों ही और मजबूत हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगा कि गठबंधन के घटक दल राज्य-विशेष के लिए संसाधनों से अधिक कुछ नहीं मांगेंगे और उन्होंने उम्मीद जताई कि इन चुनाव नतीजों के बाद आर्थिक विषयों और नीतियों पर अ?धिक ध्यान दिया जाएगा। इस बात को लेकर डर जरूर दिखा कि कहीं सरकार का झुकाव लोकलुभावन नीतियों की तरफ तो नहीं बढ़ेगा। सरकार की नीतियों में निरंतरता दिखेगी या इनमें भटकाव आएगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आसन्न बजट पर सबकी नजरें रहेंगी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में लोकलुभावन नीतियों के बजाय सार्वजनिक निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। क्या यह सिलसिला जारी रह पाएगा? क्या सरकार लोकलुभावन नीतियों से दूरी बरतेगी? सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जो नीतियों में निरंतरता जारी रहने का संकेत है। हां, यह जरूर है कि रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यह मतदाताओं की एक प्रमुख चिंता थी। उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार शिक्षा एवं हुनर विकास के लिए अधिक प्रयास करेगी। निवेशकों के मन में यह बात बार-बार कौंध रही थी कि भाजपा अपने उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन के लिए किन कारणों को जिम्मेदार ठहराएगी। क्या इस विषय पर मंथन सरकार की नीति की दिशा बदलेगी? क्या हम सार्वजनिक निवेश घटाकर राजस्व व्यय की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे? क्या सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के संकल्प के साथ समझौता करेगी? क्या बड़े कारोबारी समूहों को बदनाम किया जाएगा? क्या सरकार अनुकूल नीतियां तैयार कर दिग्गज वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर पाएगी? सभी यह भी मान रहे थे कि सरकार नए उत्साह के साथ तत्काल अपना काम शुरू कर देगी। नीतिगत सुधारों को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं और सभी ने सुन रखा था कि मंत्रालयों को शुरुआती 100 दिन की योजनाएं तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय बाजार पहले से ही 7-8 फीसदी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और 15 फीसदी से अधिक प्रति शेयर आय वृद्धि के अनुमान पर बढ़ चुका है। मूल्यांकन ऊंचे स्तर पर बरकरार रखने के लिए हमें आगे बेहतर नतीजे देने होंगे। सरकार की गति धीमी पड़ी तो इसे नकारात्मक नजरिये से देखा जाएगा और गठबंधन राजनीति को लेकर चिंता फिर बढ़ जाएगी। भारत में रकम झोंकने की राह में ऊंचा मूल्यांकन चिंता का एक कारण है। भारत अब दुनिया में स्पष्ट रूप से सर्वाधिक महंगा बाजार बन गया है। घरेलू निवेशक बाजार में तेजी ला रहे हैं और ज्यादातर लोग समझ रहे हैं कि स्थानीय निवेशकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है मगर यह चिंता फिर भी सता रही है कि यह सिलसिला थम गया तो क्या होगा।

जैव उर्वकों से बढ़ती है फसल की गुणवत्ता

फसल उत्पादन में उर्वरकों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। आधुनिक सघन खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य कृषि रसायनों के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए असंतुलित प्रयोग से भूमि की संरचना तथा उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बात ने हमें यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि हम प्रकृति के इस महत्वपूर्ण संसाधन भूमि की उर्वरता संरचना तथा पर्यावरण को लम्बे समय तक कैसे बचाये रखें।

दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रवेश होने से हमारे आगे न केवल अधिक फसल उत्पादन करने की बल्कि उत्कृष्ट गुणवत्ता बनाए रखने की भी चुनौती है। जैव उर्वरकों को पूरक के रूप में प्रयोग करने से रासायनिक उर्वरकों की क्षमता बढ़ती है साथ-साथ फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है।

क्या हैं जैव उर्वरक?

पर्यावरण के संरक्षण, भूमि की संरचना तथा उर्वरता को बचाए रखते हुए अधिक उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणुओं के उर्वरक तैयार किये हैं जो वायुमण्डल में उपलब्ध नत्रजन को पौधो को उपलब्ध कराते है तथा भूमि में पहले से मौजूद फास्फोरस आदि पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।

यह जीवाणु प्राकृतिक हैं, रासायनिक नहीं इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक का विकल्प नहीं है। इन्हें रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में प्रयोग करने से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते है।

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभकों) द्वारा उत्पादित राइजोबियम कल्चर, एजेटो वैक्टर, एसीटो वैक्टर और पी.एस.एम. उपयोगी जैव उर्वरक हैं।

राइजोबियम कल्चर

इसके जीवाणु पौधों की जड़ो में गांठ बनाकर रहते हैं तथा वायुमण्डल में उपस्थित नाइट्रोजन को शोषित कर भूमि में स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते है। ये जैव उर्वरक दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उर्द, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन आदि फसलों में उपयोग में लाये जाते है। प्रयोग के लिए यह ध्यान रखना चाहिये कि ये फसल विशेष के लिए अलग-अलग होते हैं और फसल का नाम पैकेट पर अंकित होता है।

एजेटो बैक्टर

यह जैव उर्वरक सभी अनाज गेहूं, जौ, जई ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सब्जी की फसलों, फूलों तथ अन्य फसलों जैसे गन्ना, कपास, तम्बाकू एवं पटसन आदि में प्रयोग में लाया जाता है। इसके जीवाणु पौधों की जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमण्डल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधो को उपलब्ध कराते हैं।

एसीटो बैक्टर

यह जैव उर्वरक गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पाया गया है। जो गन्ने की फसल के लिए नत्रजन वाले उर्वरकों की लगभग 25-30 प्रतिशत की बचत करने में सहायक होता है, इसके प्रयोग से गन्ने की फसल से प्राप्त होने वाली चीनी के परते में 1-2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

पी.एस.एम.

भारत की 80 से 90 प्रतिशत भूमि में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भूमि में फास्फोरस तत्व की पूर्ति हेतु प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा का लगभग 35-40 प्रतिशत भाग ही फसल उपयोग में ला पाती है, शेष भाग अघुलनशील अवस्था में भूमि के अन्दर बेकार पड़ा रहता है। जबकि फास्फेटिक उर्वरकों पर कृषकों की सबसे ज्यादा लागत आती है। पी.एस.एम. भूमि में अघुलनशील अवस्था में उपस्थित फास्फोरस तत्व को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है। यह सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है।

बीज उपचार

इस विधि द्वारा राइजोबियम, एजोटो बैक्टर एवं पीएसएम जैव उर्वरकों का प्रयोग दलहन की फसलों, गेहूं, जौं, मक्का, बाजरा, राई, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि फसलों में किया जाता है। इस विधि में एक पैकेट का घोल लगभग 200-500 मिली. पानी में बनाकर 10 किलो बीज के ऊपर एक साथ छिड़क कर हाथ से अच्छी तरह मिलायें ताकि जैव उर्वरक की एक पतली परत बीज के सभी दानों पर बन जायें। उपचार के तुरन्त बाद छाया में सुखाकर बीज की बुवाई कर दें।

भूमि उपचार

इस विधि द्वारा एजेटो बैक्टर, एसीटो बैक्टर एवं पीएसएम जैव उर्वरकों का प्रयोग सभी खाद्यान्नों की फसलों, गन्ना, तिलहन फसलों, सब्जी फसलों, फूलों आदि में किया जा सकता है। इस विधि में जैव उर्वरकों की लगभग 2-5 कि.ग्रा. मात्रा को 100 कि.ग्रा. अच्छी प्रकार सड़ी गोबर की खाद या कम्पोस्ट में मिलाकर खेत की तैयारी के समय अन्तिम जुताई से पूर्व खेत में एक साथ छिड़क कर मिट्टी में मिला दें।

कन्द उपचार

आलू की फसल में एजोटो बैक्टर व पीएसएम का उपयोग करने के लिये प्रति हे.2 कि.ग्रा. जैव उर्वरकों को 20-25 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें बीज को 5 मिनट के लिये डुबोकर बुवाई करें। गन्ने की फसल में एसीटो बैक्टर के प्रयोग में लगभग 5 किलो जैव उर्वरक प्रति.हे. की आवश्कता पड़ती है।

जड़ उपचार विधि

यह विधि रोपाई वाली फसलों में प्रयोग की जाती है। इस विधि में 1-2 किग्रा. जैव उर्वरकों को 10-20 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिये रोपाई हेतु पौधों को रोपाई से पूर्व 10 मिनट के लिये जड़ो को डुबोकर रोपाई की जाती है।

जैव उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियाँ

यह जीवित जीवाणुओं का मिश्रण है, इसलिए इन्हें तेज धूप, उच्च तापक्रम से सदैव बचाये रखें, अन्यथा उनके जीवाणु मरने शुरू हो जाते है। गर्मियों में भण्डारण के लिये मकान के कोने में रेत के अन्दर घड़े मे रख दें। रेत पर पानी छिड़कर कर भिगोते रहें। इस प्रकार अधिक तापक्रम के प्रभाव से जैव उर्वरकों को बचाया जा सकता है। पैकेट खरीदते समय उनकी निर्माण तिथि अवश्य देख लें और उनका उपयोग अन्तिम तिथि से पूर्व कर लें। पैकेट उपयोग के समय ही खोलें।

सदैव ध्यान रखें कि ये रासायनिक उर्वरकों के विकल्प नहीं है। फसलों की पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति इनका रासायनिक एवं कार्बनिक खादों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर करें। फसल के लिये निर्धारित जैव उर्वरक ही प्रयोग करें। बीज शोधन में यदि रसायन का प्रयोग करना हो तो इनकी प्रयोग की जानी वाली मात्रा को निर्धारित मात्रा से दोगुना कर देना चाहिये और पहले रसायनों को प्रयोग करें उसके उपरान्त ही जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक खादों में मिलाकर इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। जैव उर्वरकों को सड़ी नमी युक्त गोबर की खाद अथवा कम्पोस्ट खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करने से ही बेहतर परिणाम प्राप्त होते है। कृभको द्वारा हजीरा संयंत्र (गुजरात) वाराणसी संयंत्र (उत्तर प्रदेश) लांचा संयंत्र (महाराष्ट्र) में कुल 650 मैट्रिक टन जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। ये जैव उर्वरक कृषक भारती सेवा केन्द्रों एवं सहकारी समितियों से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृभकों के नजदीकी प्रतिनिधि से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने संबंधी याचिका खारिज

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत है। एकल न्यायाधीश ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है और उसने संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर उस पर नजर रखने का निर्देश दिया। कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट वह थे।

हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 5 महीने बाद एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक, रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार (3 जुलाई) को हुई सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंपाई सोरेन को समन्वय समिति का चेयरमैन बनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, अभी इसकी औऐपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में एक बार फिर हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शामिल हुए।

हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली। हाथरस भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वकील विशाल तिवारी ने खटखटाया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को दो जुलाई की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें। याचिका में भगदड़ की घटनाओं से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को ब्लॉक/तहसील से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति जिला स्तर पर देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग में मची भगदड़ में 124 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।

राजभवन के सामने धरने पर बैठेंगे शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकता हाईकोर्ट ने राजभवन के सामने चार घंटे तक धरने पर बैठने की अनुमति दे दी है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि विपक्ष के नेता 14 जुलाई को राजभवन के सामने धरना दे सकेंगे। कोर्ट ने इसकी सशर्त इजाजत दे दी है। राज्य ने सूचित किया है कि उन्हें निश्चित दिनों और निश्चित समय पर भाजपा के शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने धरने की इजाजत दे दी। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अमृता सिंह की बेंच में शुभेंदु अधिकारी के मामले की सुनवाई हुई। राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर शुभेंदु अधिकारी अगर रविवार 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से राजभवन के सामने धरने पर बैठते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम चार घंटे तक किया जा सकता है। राज्य के बयान के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु उस दिन तय जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

सांसद अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को शपथ लेने को तैयार

नईदिल्ली। खालिस्तान समर्थक नेता और खडूर साहिब के नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने उनके शपथ ग्रहण के लिए रास्ता साफ कर दिया है। पंजाब सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए अमृतपाल को डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से दिल्ली लाए जाने की संभावना है। विशेष रूप से पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक अनुरोध भेजा था, जिसमें खडूर साहिब के निर्वाचित सांसद ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग की थी। सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अमृतपाल के लिए आवश्यक सभी चीजें पूरी हो चुकी हैं। वह 5 जुलाई को शपथ लेंगे और डिब्रूगढ़ जेल वापस लाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट, पीएम नरेंद्र मोदी बोले- जवाब सुनने की हिम्मत नहीं

झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत नहीं होती : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गइबंधन इंडिया के घटक दलों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट किया। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच विपक्ष के नेता को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाए।

दरअसल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे। हालांकि, सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देने की मांग की।

पीएम मोदी ने नारेबाजी के बीच अपना भाषण जारी रखा। यह कुछ समय तक चलता रहा और खरगे बार-बार बोलने की अनुमति देने की गुहार लगाते रहे। जब अनुमति मिली, तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। धनखड़ ने उनके वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि यह संविधान का अपमान है। मोदी ने भी वॉकआउट की निंदा की और कहा कि वह कोई अंक हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार के प्रदर्शन का लेखा-जोखा देने के लिए बाध्य हैं।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने उनसे आग्रह किया कि विपक्ष के नेता को बिना किसी व्यवधान के बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया तो पीएम को भी ध्यान से सुना जाए। पर, आज उन्होंने सदन को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने गरिमा को पीछे छोड़ा है। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। उन्होंने मेरा या आपका अपमान नहीं किया, उन्होंने संविधान की शपथ का अपमान किया है। भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता। मैं उनके आचरण की निंदा करता हूं। यह एक ऐसा अवसर

है, जहां उन्होंने भारतीय संविधान को चुनौती दी है। उन्होंने भारतीय संविधान की भावना का अपमान किया है, उन्होंने ली गई शपथ का अनादर किया है। भारतीय संविधान आपके हाथों में पकड़ने वाली चीज नहीं है, यह जीवन जीने की पुस्तक है। मुझे उम्मीद है कि वे आत्मनिरीक्षण करेंगे और कर्तव्य के उस मार्ग पर चलेंगे।

इस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। सत्य से मुकाबला करना इसके लिए जिनके हौसले नहीं हैं, उनमें बैठकर के इतनी चर्चा के बाद अपने द्वारा ही उठाए हुए सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली-मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं है। नारेबाजी, हो-हल्ला और मैदान छोड़कर भाग जाना... यही उनके नसीब में लिखा हुआ है।

उन्होंने सभापति से कहा कि आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं, 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, उसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गईं, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का हौसला भी नहीं था, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, मैं यहां डिबेट पर स्कोर करने नहीं आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब देने आया हूं। देश की जनता को मेरे पल-पल का हिसाब देना, मैं अपना कर्तव्य मानता हूं।

राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम इसलिए बाहर आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताईं। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा था, जब वह संविधान के बारे में बोल रहे थे आज जो संविधान को बचाने के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं...तब मैंने कहा कि आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं सिर्फ यह स्पष्ट कर रहा था कि कौन लोग संविधान के पक्ष में थे और कौन संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने (आरएसएस) संविधान का विरोध किया है, उन्होंने बीआर अंबेडकर और पंडित नेहरू का पुतला जलाया। वह बार-बार कहते हैं कि हमने बीआर अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने वहां (लोकसभा में) यह कहा था और वह आज भी यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता था कि बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है और आरएसएस ने क्या कहा है और ऑर्गनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो सब बताना चाहता था।

मणिपुर को भड़काने वाले अपनी हरकतें छोड़ें, पेपरलीक पर विपक्ष को घेरा

राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले पांच साल में जितना काम किया है, उतना काम करना होता तो कांग्रेस को 20 साल लग जाते। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए 10 साल निरंतर प्रयास किए गए हैं। बिना रुके, बिना थके प्रयास किए गए हैं। उसकी चर्चा देश में कम हुई है, लेकिन परिणाम व्यापक रहे हैं। उन्होंने पेपरलीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी के बाद से ये निरंतर चलता रहा है। हम राज्यों के साथ इसे हल करते जा रहे हैं। ये नॉर्थईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे जो लड़ाई लड़ते रहते थे, आज उनको साथ लेकर स्थायी समझौते हो रहे हैं। जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं, वे अदालत में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यायतंत्र में भरोसा बढ़ना महत्वपूर्ण बात है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटीं, 11 हजार से ज्यादा स्न्रद्धक्र की गईं हैं, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा जब मणिपुर ही रिजेक्ट करेगा उन लोगों को। जो लोग मणिपुर को, मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि वहां सामाजिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये ना भूलें कि इन्हीं हालातों की वजह से इस छोटे से राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। कुछ तो वजह होगी, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां हरकतें हो रही हैं। हमें समझदारी के साथ स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहें, हम सबका साथ लेने को तैयार हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने और शांति लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पेपरलीक पर कहा कि हम चाहते थे कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं।

कांग्रेस के एक तिहाई सरकार वाले तंज पर पीएम मोदी का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर भी तंज कसा। दरअसल, लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद से ही वे इस सरकार को एक तिहाई सरकार कह रहे थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें सत्ता में 10 साल तो हो गए और आपके हिसाब से अभी 20 साल बाकी हैं। आपके मुंह में घी-शक्कर। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रही है और विजय भी स्वीकार हो रही है। कांग्रेस के कुछ साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब से नतीजे आए, तब से कांग्रेस के एक साथी को मैं देख रहा था। उनकी पार्टी उनको समर्थन नहीं कर रही थी, लेकिन वे अकेले ही झंडा लेकर दौड़ रह थे। मैं कहता हूं कि वह जो कहते थे, उनके मुंह में घी शक्कर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार-बार ढोल पीटा था कि एक तिहाई सरकार। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है। हमारे 10 हुए हैं। 20 और बाकी हैं। एक तिहाई हुआ। एक तिहाई हुआ है और दो तिहाई बाकी है। इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में घी शक्कर। इससे पहले जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में पीएम मोदी ने खुद को मुद्दा बनाया और खुद को भगवान बताया। वह खुद अपनी सीट डेढ़ लाख वोट से ही बचा सके। उन्हें जनादेश भी नहीं मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड हार हुई है। 400 पार का नारा लगाया और उससे बहुत दूर रह गए। यह मोदी की हार है। वह पीएम नहीं, बल्कि एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 सीरीज के लिए हरारे पहुंची भारतीय टीम

नईदिल्ली। कप्तान शुभमन गिल की अगुआई और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए)के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में युवा भारतीय क्रिकेट टीम छह जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए यहां पहुंच गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में टीम को अपने सामान के साथ हवाई अड्डे से बाहर निकलते देखा गया।

टीम मंगलवार को मुंबई से रवाना हुई थी जबकि अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी के रूप में जुड़े हुए गिल ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क से यहां पहुंचे। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने मंगलवार रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''हम टी20 विश्व कप चैंपियन भारत का स्वागत करते हैं।'' श्रृंखला के दौरान भारत के लिए पदार्पण करने वाले शीर्ष क्रम के युवा बल्लेबाज रियान पराग ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि उनका बचपन से ही इस तरह (राष्ट्रीय टीम के साथ) यात्रा करने का सपना था।

पराग ने कहा, ''भारत की जर्सी पहनने और टीम के साथ यात्रा करने का अनुभव अलग होता है। असम से आने के कारण मेरा सपना भारत के लिए खेलना था। मैं वाकई बहुत खुश हूं। जब मैं अपना पहला मैच खेलूंगा तो जिम्बाब्वे के साथ मेरा एक खास रिश्ता होगा।'' उन्होंने कहा, ''यह उस मैदान और मेरे लिए एक खास पल होगा, जो बहुत पवित्र होगा।'' पराग ने कहा, ''मेरा पासपोर्ट खोने के बाद हम आखिरकार 20 घंटे की यात्रा के बाद यहां पहुंचे हैं। अब मैं इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'' एक और नए खिलाड़ी मध्यम गति के गेंदबाज तुषार देशपांडे ने कहा कि राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है और देश के लिए खेलना बहुत खास बात है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 545 अंक चढ़ा 80 हजार के करीब बंद

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मजबूत रुझानों के बीच बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में भारी खरीदारी के बाद बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार इंट्रा-डे ट्रेड में ऐतिहासिक 80,000 का स्तर पार किया, जबकि निफ्टी बुधवार को 162 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 632.85 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर दिन में पहली बार 80,074.30 के रिकॉर्ड इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। बाद में इंडेक्स मामूली रूप से फिसलकर 80,000 के स्तर के करीब 79,986.80 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 545.35 अंक या 0.69 प्रतिशत ऊपर है। वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी 162.65 अंक या 0.67 प्रतिशत चढ़कर 24,286.50 के नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया। दिन के दौरान, यह 183.4 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 24,307.25 के नए इंट्राडे रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया।

एचडीएफसी बैंक में क्वांट म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया निवेश

नईदिल्ली। क्वांट म्यूचुअल फंड ने प्राइवेट बैंकों में अच्छी-खासी अंडरवेट पोजीशन के बावजूद एचडीएफसी बैंक में अपना अलोकेशन बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब यह प्राइवेट बैंक ज्यादातर स्कीम्स में टॉप-2 होल्डिंग्स में शामिल हो गया है। एचडीएफसी बैंक के अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ज्यादातर स्कीम में टॉप होल्डिंग्स में शामिल हैं। गौरतलब है कि ब्लू चिप सूचकांकों (निफ्टी50) और सेंसेक्स में बैंकों का सबसे ज्यादा वेट होता है और इसमें भी एचडीएफसी बैंक का बड़ा हिस्सा है। इसलिए, इस स्टॉक के कमजोर परफॉर्मेंस ने इन इंडेक्सों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण असर डाला। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से दो में ज्यादातर लार्जकैप और बैंकिंग सेक्टर फंडों ने बेंचमार्क इंडेक्सों के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है।

रियल एस्टेट में निवेश तीन साल के उच्च स्तर पर

नईदिल्ली। इस साल पहली तिमाही में सुस्त शुरुआत के बाद दूसरी तिमाही में रियल एस्टेट में निवेश ने गति पकड़ ली है। दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र में संस्थागत निवेश 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस निवेश में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी औद्योगिक व वेयरहाउसिंग सेक्टर की रही। दूसरी तिमाही में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 81 फीसदी रही। घरेलू निवेशकों ने भी पिछले साल की दूसरी तिमाही से 2.8 गुना अधिक निवेश किया। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म कोलियर्स के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जो 2021 के बाद से किसी भी तिमाही में सबसे अधिक है। जाहिर है तिमाही आधार पर निवेश तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में निवेश में 154 फीसदी इजाफा हुआ है।

जापान ने दो दशक में पहली बार जारी किए नए बैंक नोट

टोकयो। जापान ने दो दशक में पहली बार बुधवार को नए बैंक नोट जारी किए। इनमें जालसाजी से निपटने के लिए '3-डी होलोग्राम' प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए नोट की अत्याधुनिक जालसाजी-रोधी विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए इसे ''ऐतिहासिक'' करार दिया। बैंक ऑफ जापान में उन्होंने पत्रकारों से कहा, '' मुझे उम्मीद है कि लोगों को नए नोट पसंद आएंगे और वे जापानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे।'' स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, नए नोट के साथ पहले से चलन में मुद्रा भी वैध रहेगी। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा ने कहा, ' हालांकि दुनिया नकदी रहित लेन-देन की ओर बढ़ रही है, लेकिन हमारा मानना है कि कहीं भी तथा कभी भी सुरक्षित भुगतान के लिए नकदी अब भी महत्वपूर्ण है।''

शेयर बाजार की ऊंचाई और आर्थिक वृद्धि

डॉ. जयंतीलाल

दुनिया की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नयी गठबंधन सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों, सुधारों और विकास की डगर पर आगे बढ़ने से भारत की विकास दर में वृद्धि, शेयर बाजार की नयी ऊंचाई तथा वैश्विक परिदृश्य पर भारत की अहमियत बढ़ते हुए दिख रही है। बीते 14 जून को वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में नीतिगत सुधार जारी रहेंगे। इससे अगले पांच वर्षों के दौरान विकास और इक्विटी रिटर्न प्रभावित होगा। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि सरकार महंगाई की आक्रामकता पर ध्यान देना जारी रखेगी।

मूडीज ने अगले एक वर्ष में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन सकारात्मक रहने का अनुमान भी जताया है तथा कहा है कि आगामी 12 महीनों के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का मानक सूचकांक सेंसेक्स 82 हजार के स्तर के पार जा सकता है और इसमें मौजूदा स्तर से 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन सबके साथ-साथ एजेंसी की रिपोर्ट में आने वाले दिनों में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की उम्मीद की गयी है। इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2025-26 तक आय वृद्धि पूर्वानुमान के साथ कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी, जो आम सहमति से 500 आधार अंक या पांच प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं, दुनिया में अगला दशक भारत का होगा। वैश्विक वृद्धि में भारत की भागीदारी करीब 20 प्रतिशत होगी। दुनियाभर में भारत की सेवाओं और वस्तुओं की बढ़ती मांग से इसमें मदद मिलेगी। इससे भारत में

मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि होगी। देश के उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र में नयी सरकार के बनने के बाद भारतीय शेयर बाजार की ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बना है। जहां भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अब 5.21 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, वहीं हांगकांग के शेयर बाजार का पूंजीकरण घटकर 5.17 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। देश की नयी सरकार से देश और दुनिया में विकास व सुधारों की उम्मीद बढ़ी है। पिछले दिनों प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ने मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेज आर्थिक सुधार और बढ़ती राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर से बदलकर सकारात्मक कर दिया है। इस एजेंसी का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 फीसदी सालाना रही है और अब यह दर अगले तीन साल में लगातार सात फीसदी के करीब होगी।

भारत के लिए सबसे ठोस लाभ जी-7 की उस प्रतिबद्धता से उपजा, जिसमें कहा गया कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइएमइसी) को बढ़ावा दिया जायेगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा गत वर्ष भारत में जी-20 शिखर बैठक के समय की गयी थी। जी-7 सम्मेलन में कहा गया है कि खासतौर पर इस आर्थिक गलियारे को मूर्तरूप देने के लिए समन्वय और वित्तपोषण पर जोर दिया जायेगा। इस आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलमार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गयी है, जिससे एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। आइएमइसी को समान विचारधारा वाले देशों ने चीन की बेल्ट-रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) के समक्ष रणनीतिक प्रभाव हासिल करने की पहल के रूप में पेश किया है। यह महत्वपूर्ण है कि जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की बढ़ी अहमियत से चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नये वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में और उभरकर सामने आयेगा।

पहली बार किडनी की नस में सौ प्रतिशत रूकावट का लेजर एक्जाइमर विधि से एसीआई में सफल उपचार

रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में 66 वर्षीय एक मरीज के किडनी को खून की आपूर्ति करने वाली बायीं धमनी में सौ प्रतिशत रुकावट तथा हृदय की मुख्य नस में 90 प्रतिशत रुकावट का एक्जाइमर लेजर विधि से सफल उपचार किया गया। उपलब्ध मेडिकल लिटरेचर के अनुसार विश्व में लेजर एंजियोप्लास्टी द्वारा किडनी की नस के पूर्ण ब्लॉक के उपचार का यह पहला केस है। एसीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुए इस उपचार में मरीज के किडनी की धमनी यानी रीनल आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी का एक साथ उपचार कर मरीज को रीनल फेल्योर और हार्ट फेल्योर होने से बचा लिया गया। इन दोनों इंटरवेंशनल प्रोसीजर को क्रमशः लेफ्ट रीनल आर्टरी क्रॉनिक टोटल ऑक्लूशन एवं इन स्टंट री-स्टेनोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। इस केस में पहली बार रीनल का 100 प्रतिशत ऑक्लूशन (रुकावट) था जिसके कारण बी. पी. कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। किडनी खराब हो रही थी। समय पर इलाज नहीं होता तो किडनी फेल हो जाती। डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने केस के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मरीज के किडनी को खून की आपूर्ति करने वाली दोनों नसों में ब्लॉकेज था। एक में 100 प्रतिशत ब्लॉकेज/रुकावट था एक में 70-80 प्रतिशत ब्लॉकेज था। लेफ्ट रीनल आर्टरी जहां से शुरू होती है, वहीं मुख्य ब्लॉकेज था। इसके कारण खून का प्रवाह बिल्कुल बंद हो चुका था। इसके साथ ही मरीज के हृदय की मुख्य नस में ब्लॉकेज था जिसके लिए उसको 2023 में निजी अस्पताल में स्टंट लगा था जो बंद हो चुका था। यह स्टंट पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। इन सब समस्याओं के कारण मरीज को हार्ट फेल्योर हाइपरटेंशन, सांस लेने में तकलीफ और बी. पी. कंट्रोल में नहीं आ रहा था।

ऐसे किया उपचार- सबसे पहले लेफ्ट रीनल आर्टरी जो 100 प्रतिशत ब्लॉक थी, उसमें कठोर ब्लॉकेज होने की वजह से एक्जाइमर लेजर से उसके लिए रास्ता बनाया फिर बैलून से उस रास्ते को बड़ा किया जिससे उसमें स्टंट लगाकर उस नली को पूरी तरह खोल दिया गया और नार्मल फ्लो को किडनी में वापस चालू किया गया। ब्लॉकेज खोलने के साथ ही बी. पी. में परिवर्तन आने शुरू हुए और बी. पी. कम हो गया। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिये स्टंट को देखकर यह कन्फर्म किया गया कि वह ठीक से अपने स्थान पर स्थापित हुआ है या नहीं।

पूर्व में हुई एंजियोप्लास्टी के कारण हृदय की बायीं साइड की मुख्य नस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डाले गये स्टंट के अंदर 90 प्रतिशत से भी ज्यादा रुकावट पायी गयी। इसको भी पहले लेज़र के जरिये ब्लॉकेज खोलकर रास्ता बनाया गया। फिर बैलून करके उस रास्ते को बड़ा किया गया फिर इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड के जरिए स्टंट ब्लॉकेज के क्षेत्र को देखा। चूंकि रूकावट स्टंट के साथ-साथ स्टंट के बाहर की थी, इस वजह से एक नया स्टंट डालकर उस रूकावट को खोलने का निर्णय लिया गया। एक अतिरिक्त स्टंट डालकर दोनों रुकावट का इलाज किया गया। आईवीयूएस करके पूरी प्रक्रिया की वास्तविक वस्तुस्थिति को देखा। अंततः दोनों प्रक्रिया सफल रही। मरीज अब ठीक है तथा डिस्चार्ज लेकर घर जाने को तैयार है।

बाबू भैया की कलम से

जीवन की जगह सीखा मृत्यु का पाठ, ये कैसा सत्संग

जीवन जीने की कला सिखाने हो रहे बाबाओं के सत्संग में यदि 116 लोगों का जीवन समाप्त हो जाए तो इसे क्या समझा जाए। ये बाबा जीवन जीना सीखा रहे हैं या मरना। प्रचार- प्रसार में लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। पोस्टरों के माध्यम से अपनी महानता व उत्कृष्टता का बखान करने वाले बड़े बड़े होर्डिंग व पोस्टरों से पूरा शहर व प्रदेश को पाट दिया जाता है। इस प्रकार किये जाने वाले भव्य आयोजनों में सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं। कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा यह स्पष्ट नहीं होता। 116 लोगों जिनमें अधिकांश माताएं,बहने थी असमय काल कलवित हो गए। जिम्मेदार कौन है,यह बताने में शासन-प्रशासन-पुलिस प्रशासन अक्षम साबित हुआ है। बाबा के लिए सेवादारों द्वारा रास्ता बनाने की गई धक्का मुक्की के फलस्वरूप ,यह बड़ी घटना हुई। कीचड़ वाले असुरक्षित स्थान पर आयोजन था। कारिंदों की धक्का मुक्की के कारण भगदड़ मची। लोग भागे , महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। बुजुर्ग महिलाएं धक्का मुक्की सहन नहीं कर पायीं। फिसलन में फिसल कर गिरी और भागती भीड़ ने अपने पैरों से 116 जिंदगियों को रौंद दिया। किसी की मां,किसी की बहन,किसी की घरवाली,किसी का रिश्तेदार जो पैरो तले आया दुनिया से चला गया। साथ ही सैकड़ों परिवार को बिखेर गया। गए थे जीवन का ज्ञान प्राप्त करने,मौत गले लगा कर निर्जीव घर लौटे। हाहाकार मचा, लेकिन इन सब बातों से बाख़बर होते हुए भी बाबा वहां से भाग निकले। यानी सम्मेलन स्थल से गायब हो गए। घटना घट गई तब बाबा की असलियत अखबारों ने बयान करनी शुरू की। नारायण हरि उनका असली नाम है वे बाबा के नाम मशहूर होने की मार्केटिंग करके प्रवचन करने के पहले यूपी की पुलिस में 18 साल सेवाएं दे चुके हैं। भोले बाबा के नाम से प्रसिद्धि पाने के पहले उनका असली नाम नारायन सरकार उर्फ सूरजपाल जाटव था। वे यूपी के एटा के रहने वाले हैं। 17 साल पहले नौकरी से वीआरएस लिया। सत्संग शुरू कर दिया, साथ में अपनी पत्नी को भी मंच से जोड़ लिया। अनुयायियों में अधिकांश लोग ओबीसी,एसटी,एससी वर्ग के लोग अधिक है। संख्या में धीरे धीरे अनुयायी लाखों में पहुंच गए। हर महीने के पहले मंगलवार को प्रवचन शुरू हो गया। लाखों खर्च होने लगे। स्पॉन्सर भी मिलने लगे। सत्संग की सारी व्यवस्था सेवादार सम्हालते हैं। हाथरस के आयोजन में 12 हजार सेवादार लगे थे। व्यवस्था वे जनता की करते तो यह घटना शायद नहीं घटती। सेवादारों ने जनता की जगह बाबा की व्यवस्था पर ध्यान दिया। जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। सेवादारों ने खुद ही भक्तगणों के बीच बाबा के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने जनता से धक्का- मुक्की की। फलस्वरूप यह गंभीरतम घटना घट गई। एक पुरुष व एक मासूम बच्चे के अतिरिक्त मरने वालों में सभी महिलाएं थी। भक्ति का यह जुनून इनके भरे पूरे परिवार को भारी पड़ गया। घटना के बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा गया। एसडीएम व पुलिस के बयान से ही पता चल जाता है कि आयोजन को हल्के ढंग से लिए गया था। एसडीएम ने कहा कि 50 हजार भीड़ जुटने की बात कही गई थी। 80 हजार भक्तगण पहुंच गए। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें आयोजकों से कार्यक्रम का जो पत्र मिला ,उसमें भीड़ का कालम खाली था। यूपी के सीएस ने एक कदम आगे जाकर कहा कि 80000 लोगों की अनुमति थी,लेकिन अधिक भीड़ शामिल हुई। इन बयानों की जद में ही सोच सकते हैं कि कितना विरोधाभाष है। एसडीएम ने कहा, 50 हजार की भीड़ आएगी बताया गया था। थाने ने कहा भीड़ की संख्या का कालम ही खाली था। यूपी के सीएस ने कहा 80 हजार की अनुमति थी, उससे ज्यादा लोग आ गए। पुलिस ने खाली कालम की जानकारी आयोजकों से क्यों नहीं ली। एसडीएम व सीएस की बातों में इतना विरोधाभाष क्यों है। यह जांच का विषय हो सकता है। घटना की जानकारी होने के बाद भी बाबा वहां से भाग क्यों गए। इस विषय पर एक बयान तक जारी नहीं किया। दिन में 1.30 बजे घटना घटी उसके बाद से बाबा सामने क्यों नहीं आये। भीड़ उन्हें देखने सुनने भर के लिए इकट्ठा हुई थी। जीवन जीने की कला सिखाते सिखाते मृत्यु का पाठ पढ़ा कर बाबा गायब हो गये। सत्संग के आयोजक मानव मंगल मिलन सद्भावना सामिति की कितनी जिम्मेदारी है , यह तय होना चाहिए।जांच के समय के लिए यह प्रश्न लाजिमी है। इन सारी बातों का जवाब मिलना ही चाहिए।

इन आयोजनों का दूसरा पक्ष भी देखा जाना चाहिए। पहले हम सब देखा करते थे, कि गली मोहल्लों में ऐसे आयोजन हुआ करते थे। छोटे छोटे हाथ से लिखे पोस्टर लगा दिए जाते थे। भक्तगण सुविधानुसार भजन या सत्संग सुनने आया करते थे।मोहल्ले के लोग ही चंदा करके खर्च उठा लेते थे। अपवाद छोड़ कोई स्पॉन्सर नहीं होता था। अब बाबाओं की जिस प्रकार से मार्केटिंग की जा रही है। इसके लिए लाखों की राशि खर्च करने से गुरेज नहीं होता। बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आप खोजें तो साफ हो जाती है। धर्म की राजनीति के लिए यह बड़े आयोजन करने लगे हैं। आयोजन क्रमशः छोटे से कब धीरे धीरे भव्य रूप धारण कर लिए समझ नहीं आया। इतनी भव्यता क्यों बनाई गई। इसको समझना काफी शोध करने का विषय है। फिर इन बाबाजी के तो ओबीसी,एसटी,एससी वर्ग के अनुयायी अधिक संख्या में हैं। यही राजनैतिक दलों व संस्थाओं के आकर्षण का विषय है। जहां शहद होगा वहीं चीटियां तो होंगी ही। खुद कुछ राजनैतिक दल इसमें साफ जुड़े हुए दिखाई भी दे जाते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अपने पूंजीपति समर्थकों के माध्यम से जुड़े हैं। आयोजन भव्य हो, खूब भीड़ जुटे। यह प्रयास उनका होता है। एक बार में ही धर्म के आख्यान के बीच अपने दल की भावना को जनता के बीच बाबाजी के द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। वह भी बड़ी सरलता से। बाबाओं की पूछ परख इन दिनों बढ़ी हुई है। अनेक राज्यों में तो इन्हें राज्य अतिथि का दर्जा भी दिया जा रहा है। आयोजनों में बेहिसाब राशि खर्च की जाती है। इस राशि का कितना बडा हिस्सा इन संत -बाबाओं को मिलता है, कितना आयोजकों के हिस्से में,यह आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। आम आदमी तो बस भक्ति की भावना में डूब कर जीवन जीने की कला सीखने जाता है। यह भी कि भारत की जनता 15-20 दिनों से ज्यादा किसी भी बड़ी से बड़ी घटना को भूल जाती है। इसे भी भूल जायेगी। लेकिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि इस घटना को भूले नहीं, और इसमें ऐसी कड़ी कार्यवाही दोषियों पर हो, जो भविष्य में आयोजकों व बाबाओं के लिए नजीर बने। कोई कितना भी ताकतवर या बाहुबली हो ,उसे बक्शा नहीं जाना चाहिए। यह मामला यूपी का है जहां अनेक मुद्दों पर नजीर प्रस्तुत करने वाले मुख्यमन्त्री हैं। उनसे भी भारत के लोगों को बड़ी उम्मीद है।

राज्य की 18 सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी, 3289 करोड़ का प्रावधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने आज राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए केंद्र से छत्तीसगढ़ में करीब 18 परियोजनाओं के प्रावधानों को स्वीकृति मिली है. इसके लिए केंद्र से 3289 करोड़ करोड़ रूपये राज्य सरकार को मिलेंगे. साथ ही भविष्य में प्रस्तावित 1006 किलोमीटर लंबाई के आठ कार्यों के सर्वेक्षण और छ्क्क्र के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ की जानता को लगातार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि कस्तूरमेटा से महाराष्ट्र सीमा तक डबल लेन में सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन क कार्य किया जाएगा. इसके अलावा जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग पर स्तिथ कांगेर वेली राष्ट्रीय उद्यान के भाग में डबल लेन सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य होगा.

उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना-प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के वक्त जब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आए थे तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था की हर प्रस्ताव की स्वीकृति दी जायेगी. इसके बाद एक दूसरे कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भी इस बात को स्वीकारते हुए कहा था कि जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दिया जाता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया. पूर्व में कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव नहीं मिलते थे. क्योंकि कांग्रेस की विकास में रुचि ही नहीं थी. यह राशि हमें काम करने की नियत से मिली है.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम चाहते है कि प्रदेश में नए-नए उद्योग आए और उद्योग नीति आगे बढ़े. जो निवेश करने वाले लोग हैं उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि समयबद्ध तरीके से सरकार ने सिस्टम तैयार किया है. निवेश आएगा, जोर लगेगा, प्रदेश का विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा.

फौती, नामांतरण एवं बटवारा, जैसे प्रकरणों के निराकरण के लिए गांवों में लगेंगे शिविर

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन पर अब किसानों और भू-स्वामियों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री की मंशानुरूप राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए थे। पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के भी निर्देश दिए है। राजस्व पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे: फौती, नामांतरण एवं बटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही आनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा कर प्रविष्टि एवं मौके पर ही नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराकर निराकरण करने को कहा गया है। शिविर स्थल पर ही बी-1, खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

16वें केंद्रीय वित्त आयोग का छत्तीसगढ़ राज्य भ्रमण

रायपुर। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल का छत्तीसगढ़ राज्य में तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में दिनांक 11 से 13 जुलाई 2024 हेतु तय हुआ है। आयोग में 12 सदस्यीय दल अंतर्गत अध्यक्ष के अतिरिक्त 04 सदस्य— अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, मनोज कुमार पांडा, डॉ सौम्य कांति घोष तथा आयोग के सचिव रित्विक रंजनम पांडेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा , संयुक्त संचालक राघवेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति में राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा आयोग के समक्ष राज्य के आर्थिक, वित्तीय, अधोसंरचना विकास तथा राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतिकरण व ज्ञान प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन उपरांत से उत्पन्न प्रभाव की स्थिति से आयोग को अवगत कराते हुए आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान संबंधी मांग पत्र भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अनुशंसाएं केंद्र सरकार को अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएंगी।

रायपुर पुलिस की 'निजात' अभियान से अपराधों में आई कमी

रायपुर. रायपुर पुलिस की निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध लगातार प्रहार, विजिबल पुलिसिंग और अपराधियों पर सख्ती का अपराधों में कमी दिखने लगा है. अभियान के पांच माह में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के अपराधों में 8 फीसदी की कमी आई है. मारपीट में 4%, हत्या व हत्या के प्रयास में 15%, चाकूबाजी में 40%, बलात्कार में 10, छेड़छाड़ में 23 फीसदी व चोरी में 4त्न की कमी आई है. आबकारी एक्ट और ड्रग-विरोधी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 3,682 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों में 451 आरोपियों को जेल भेजे गए. नशे के विरुद्ध जारी जनजागरुकता के तहत 5,12 कार्यक्रम किए गए. थानों में नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग की जा रही है. इस वर्ष फरवरी माह से डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देशन में आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह के मार्गदर्शन में अवैध नशा के विरुद्ध अभियान निजात चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को देंगे एक लाख की प्रोत्साहन राशि का और स्कूटी खरीदने एक लाख का चेक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरूवार 04 जुलाई को पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रूपए की राशि का चेक प्रदान करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एक लाख रूपए तथा स्कूटी क्रय के लिए दी जाने वाली एक लाख रूपए का चेक मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री सवेरे 10.30 बजे अपने निवास कार्यालय में श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 13 बच्चों को कुल दो-दो लाख रूपए का चेक प्रदाय करेंगे। इसमें एक लाख रूपए का चेक स्कूटी खरीदी के लिए बच्चों को दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ज्ञात हो कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-24 में अध्ययनरत तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2023-24 में निर्माण श्रमिक के 13 बच्चे टॉप-10 सूची में है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को सुगमता से मिल रहा है खाद-बीज

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 7.72 लाख टन खाद और 6.69 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 13.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 01 जुलाई 2024 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 153 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो इसी अवधि की दस वर्षों की औसत वर्षा 182.3 मिमी से 29.3 मिमी कम है। गत वर्ष इसी अवधि में 169.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1236 मिमी है। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है.

जनदर्शन-एक सप्ताह के भीतर 5 वर्षीय नूतन की आंख का हुआ इलाज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से पांच वर्षीय नूतन ठाकुर की आंख का इलाज एक सप्ताह के भीतर हो गया है। नूतन की आंख में खेल-खेल में चोट लग गई थी जिससे उसका रेटिना खराब हो गया था। उसके पिता श्री काशी ठाकुर मुख्यमंत्री निवास में 27 जून को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और उनसे नूतन की आंख का इलाज करने के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को नूतन का बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। काशी ठाकुर आज अपनी बेटी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नूतन को दुलार, नाम पूछा और नूतन को अपना आशीर्वाद प्रदान किए। उन्होंने नूतन से कहा अच्छे से पढ़ाई करना। नूतन ने मुख्यमंत्री को बाल सुलभ सहजता के साथ गुलाब का फूल भेंट किया। श्री काशी ठाकुर भी बेटी के इलाज के लिए मिली त्वरित सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते नहीं थकते। गौरतलब है कि नूतन के पिता दुर्ग के बोरसीभाटा में रहते हैं, वे माली का काम करते हैं।

राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि राजस्व विभाग का कार्य आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप लोगों के राजस्व संबंधी कार्य पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारी इस पखवाड़े के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का अनिवार्य रूप से त्वरित निराकरण करें। श्री वर्मा कलेक्टोरेट बलौदाबाजार में जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा की राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे बहुत ही छोटे -छोटे कार्य होते है जो हर किसी से जुडा होता है। इन कामों का निपटारा समय पर कर दिया जाए तो लोगों में राजस्व विभाग के प्रति जो नज़रिया है वह सकारात्मक हो सकता है। पहले एक गांव को चिन्हांकित कर राजस्व विवादमुक्त ग्राम बनाएं। ऐसे ग्राम के पटवारी आरआई को सम्मानित भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बरसात में जिले के नदी- नालों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।

मंत्री वर्मा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। खेत में पानी भरने से धान खराब होने पर किसानों को नि:शुल्क बीज प्रदाय करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित सभी किसानों को पंजीकृत कर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बड़े सीमेंट सयंत्रों एवं खदानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलबध कराने के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सयंत्रो के द्वारा संचालित खनन इकाईयों में भी युवाओं को नियोजित कराएं। उन्होने अग्निवीर भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित करने तथा कैरियर मार्गदर्शन एवं कोचिंग की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कुछ सड़कें बहुत जल्द ख़राब होने की बात सामने आ रही है, ऐसे सड़को के निर्माणकर्ता ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बलौदाबाजार बाई पास निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को सुगमता से मिल रहा है खाद-बीज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 7.72 लाख टन खाद और 6.69 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की बौछारों के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। राज्य में अब तक 13.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 01 जुलाई 2024 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 153 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो इसी अवधि की दस वर्षों की औसत वर्षा 182.3 मिमी से 29.3 मिमी कम है। गत वर्ष इसी अवधि में 169.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1236 मिमी है। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 8.07 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 6.69 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो मांग का 68 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 13.68 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.